● वर्ष-5

● अंक-294

रायपुर, रविवार
26 जुलाई 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-8>> दिव्यांशु देवांगन का वित्त मंत्री...

छात्रों के भारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच मोहन भागवत का बड़ा संदेश

युवाओं को आदेश नहीं, आपसी सहमति की जरूरत



मुंबई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आज की युवा पीढ़ी न तो गुमराह है और न ही दिशाहीन; उन्होंने युवाओं को समझने के लिए आदेश देने के बजाय सार्थक चर्चा करने की बात कही। आरएसएस प्रमुख की ये बातें ऐसे समय में आई हैं जब दिल्ली की सड़कों पर परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर छात्रों का बड़ा विरोध-प्रदर्शन हो रहा है, जो राजधानी में पिछले कुछ सालों में हुए सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है।

विश्व मांगल्य सभा कार्यक्रम में बोलते हुए, भागवत ने पीढ़ियों के बीच बढ़ती खाई पर बात की और कहा कि आज के युवाओं को सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, जब हम युवा थे, तो वह आज्ञा मानने का दौर था। अब ऐसा नहीं है।

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी सवाल पूछने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, इसलिए माता-पिता और बड़ों के लिए उनसे जुड़ना ज़रूरी है। साथ ही, उन्होंने परिवारों के भीतर बातचीत के लिए कम होती जगह पर चिंता भी जताई। भागवत ने कहा, नई पीढ़ी सवाल पूछती है। हमें उन्हें तर्क समझाना होगा। हमें उन्हें बहुत प्यार देना होगा। हमें उनके साथ समय बिताना होगा। हमें उनसे बातचीत करनी होगी।

उन्होंने आगे कहा कि युवाओं का भरोसा जीतने के लिए बातचीत की ज़रूरत होती है, न कि आदेशों की। भागवत ने कहा, हमें नई पीढ़ी को अपनापन महसूस कराना होगा। हमें बातचीत करनी होगी। आदेश नहीं, चर्चा। हुक्म नहीं, आपसी सहमति। हालांकि भागवत ने जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शन का सीधे तौर पर ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उनके बयानों के समय ने कोई शक नहीं छोड़ा।आरएसएस प्रमुख ने अब तक सीजेपी विरोध-प्रदर्शनों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जो दूसरे राज्यों में भी फैल गए हैं। 20 जुलाई को हुई हिंसा, जिसमें संसद से कुछ ही मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ज़बरदस्त झड़प हुई थी, ने जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया है।

शुक्रवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिबल ने आरएसएस प्रमुख की चुप्पी पर सवाल उठाए। सिबल ने ट्वीट किया, मोहन भागवत जी... जंतर-मंतर पर हुई घटनाएं... पिछले एक महीने में आपकी चुप्पी आपके उपदेशों से कहीं ज़्यादा कुछ कह रही है। सीजेपी विरोध-प्रदर्शन पर ताज़ा जानकारी क्या है? प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा है।हालांकि, सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया है, भले ही उसने भविष्य में पेपर लीक को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसमें दखल दिया है और पेपर लीक व शिक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में शामिल लोगों के लिए कड़ी सज़ा सुनिश्चित करने वाला बिल लाने की घोषणा की है।प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे व्यंग्यात्मक आंदोलन सीजेपी ने सरकार के साथ बातचीत के दो दौर के बावजूद अपनी मांगों को कम करने से इनकार कर दिया है।

राष्ट्रपति ने मंजूर किया प्रधान का इस्तीफा

प्रह्लाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार



नई दिल्ली।कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को शनिवार को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। यह घटनाक्रम परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के विरोध प्रदर्शनों के बीच हुआ है। राष्ट्रपति कार्यालय ने शनिवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के माध्यम से इस नियुक्ति की पुष्टि की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। यह स्वीकृति संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत की गई है। इसी बीच, राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि वे खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री के रूप में अपना मौजूदा कार्यभार भी संभालते रहेंगे।

अधिकारियों ने कहा कि दोहरी प्रभार व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय के कामकाज में बिना किसी बाधा के निरंतरता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रपति के विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि यह परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जिससे नई व्यवस्था बिना किसी देरी के प्रभावी हो सकेगी। प्रधानमंत्री की सलाह पर इस्तीफा स्वीकार करके और साथ ही अतिरिक्त प्रभार सौंपकर राष्ट्रपति मुर्मु ने प्रधान के पद छोड़ने और प्रल्हाद जोशी के नेतृत्व में अंतरिम व्यवस्था को औपचारिक रूप दे दिया है।

युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं का सम्मान

मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट करता हूं।किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में करने का निर्णय लिया गया।



जोशी के पास पहले से हैं ये मंत्रालय

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वरिष्ठ मंत्रिमंडल मंत्री प्रल्हाद जोशी अब खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारियों के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का भी कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि इस्तीफे के बाद प्रधान ने कहा कि राष्ट्रसेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस्तीफे के बाद उनके घर पर नेताओं का तांता लग गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समेत भाजपा और एनडीए के कई बड़े नेता और मंत्री उनके घर पहुंचे और उनसे बातचीत की।

प्रधान के इस्तीफे परबोले गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री पद से विदा हो रहे हैं, तो यह उनकी दशकों के समर्पित लोक सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके उल्लेखनीय योगदान को स्वीकार करने और सराहना करने का अवसर है। छात्र आंदोलनों से उनके प्रारंभिक जुड़ाव से लेकर सार्वजनिक जीवन और शासन में उनकी विशिष्ट भूमिकाओं तक, उन्होंने निरंतर प्रतिबद्धता, अनुशासन और जनता, विशेष रूप से भारत के युवाओं की आकांक्षाओं के साथ गहरा जुड़ाव प्रदर्शित किया है।

विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्पेशल जज अनु ग्रोवर ने संभाला कार्यभार



नई दिल्ली। नीट पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के उद्देश्य से गठित दिल्ली की विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। इस अदालत की स्पेशल जज अनु ग्रोवर बलिगा ने शनिवार सुबह कार्यभार संभाल लिया, जिसके साथ ही बहुचर्चित नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई भी प्रारंभ हो गई।

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में इस विशेष अदालत के गठन को मंजूरी दी थी। अदालत का उद्देश्य नीट व अन्य व्यवसायिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल, फर्जीवाड़े और अन्य परीक्षा संबंधी आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाना है। इसके माध्यम से ऐसे संवेदनशील मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी, जिससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों का विश्वास मजबूत हो सके। इस प्रकार अब इस अदालत में नीट पेपर लीक प्रकरण सहित अन्य परीक्षा अनियमितताओं से जुड़े मामलों की नियमित सुनवाई होगी। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने से अभ्यर्थियों को समय पर न्याय मिलने और भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की उम्मीद जताई जा रही है।

जंतर-मंतर पर सीजेपी का आंदोलन समाप्त

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहा विरोध प्रदर्शन आखिरकार खत्म हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शनिवार को अपना आंदोलन तुरंत प्रभाव से वापस लेने का बड़ा एलान किया। यह घोषणा केंद्र सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत के बाद हुई। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने शनिवार को सीजेपी के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में सीजेपी के सौरव दास शामिल थे। दोनों पक्षों के बीच बातचीत का तीसरा दौर सकारात्मक रहा। वार्ता के तुरंत बाद



सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धरना समाप्त करने की घोषणा की। पार्टी ने देश भर से आए प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक अपने घर लौटने की अपील की है। सौरव दास ने सरकार से बातचीत की सारी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि हमारी दूसरी मांग यह थी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर न केवल दिल्ली में बल्कि सभी भाजपा-शासित और भाजपा-सहयोगी राज्यों में वापस ली जानी चाहिए। सरकार ने उस मांग को भी मान लिया है। साथ ही, इन्हें जल्द ही वापस ले लिया जाएगा।

दास ने कहा कि सरकार ने हमें भरोसा दिलाया है कि वह दर्ज सभी एफआईआर की कॉपी शेयर करेगी। हमारी आखिरी जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में 15 से 20 एफआईआर दर्ज की गई थीं और हमें किसी भी हाल में तीन से चार दिनों के भीतर वे कॉपी मिल जाएंगी। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि इन्हें जल्द ही वापस ले लिया जाएगा। इसे समझते हुए, हमने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। सरकार ने कहा है कि वह मंगलवार तक इसे हमारे साथ शेयर करेगी। हमें उम्मीद है कि मंगलवार तक हमें इन एफआईआर और भविष्य की किसी भी कार्रवाई के संबंध में सरकार की गारंटी मिल जाएगी।

प्रमुख समाचार

पीआईबी ने मोदी और गोयल के वीडियो को बताया फेक



नईदिल्ली। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के एआई से बने उन वीडियो की सच्चाई की जांच की है, जो छात्रों के बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि ये वीडियो एआई से बने डीपफेक हैं, जिन्हें लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया था। यूनिट ने कहा कि न तो पीएम मोदी और न ही गोयल ने क्लिप में दिखाए गए बयान दिए हैं, और साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रोपेगैंडा अकाउंट ऐसे वीडियो फैला रहे हैं। ऑडियो में हेरफेर किए गए फर्जी वीडियो क्लिप में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को राजधानी और कई अन्य राज्यों में हो रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर प्रदर्शनकारी छात्रों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए दिखाया गया है। पीआईबी ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी दुष्प्रचार करने वाले खाते प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो प्रसारित कर रहे हैं।

बिट्टू के इस्तीफे से पंजाब में नई चुनावी बिसात

जालंधर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह बिट्टू के इस्तीफे ने पंजाब की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार भाजपा अब बिट्टू को पंजाब में प्रमुख चुनावी चेहरे के रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। स्वयं बिट्टू भी संकेत दे चुके हैं कि अब उनका पूरा ध्यान पंजाब की राजनीति पर रहेगा और वह विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते होने के कारण भाजपा उन्हें अपने प्रमुख जाट सिख चेहरे के रूप में पेश करना चाहती है। इस्तीफे से एक दिन पहले बिट्टू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर पंजाब की लंबित रेलवे आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को जल्द पूरा कराने का आग्रह किया था। ऐसे में उनके पद छोड़ने के बाद इन परियोजनाओं के समन्वय पर भी नजर रहेगी। माना जा रहा है कि अब वह आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस के खिलाफ और आक्रामक राजनीतिक अभियान चलाएंगे।



राज ठाकरे ने आज तिरंगा मार्च में शामिल होने की अपील की

मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से 26 जुलाई को मुंबई में तिरंगा मार्च में शामिल होने की अपील की है। इस मार्च का मकसद नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ़ विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन करना और सरकार के रवैये की आलोचना करना है। एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, ठाकरे ने इस मार्च को छात्रों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन, आंदोलन को दबाने की सरकारी कोशिशों के खिलाफ था। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह रैली पूरी तरह से गैर-राजनीतिक है और लोगों से अपील की कि वे पार्टी के झंडे न लाएं और न ही किसी राजनीतिक नेता—खुद उनके या उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारे लगाएं। उन्होंने कहा कि यह एक तिरंगा मार्च है। यह पूरी तरह से गैर-राजनीतिक है। यहां न तो किसी पार्टी का झंडा होगा और न ही किसी पार्टी के नेताओं के समर्थन में कोई नारा लगाया जाएगा।



बिहार बंद के दौरान तेजप्रताप यादव को हिरासत में लिया

पटना। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख के और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को पुलिस ने पटना में हिरासत में लिया है। तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों के साथ विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने निकले थे। इसी दौरान पटना जंक्शन के पास पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद तेज प्रताप के समर्थकों ने आक्रोश जताया। समर्थकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आहूत बिहार बंद के दौरान समस्तीपुर में भीम आर्मी से जुड़े बंद समर्थकों ने शनिवार को पटेल गोलंबर से समाहरणालय तक जोरदार प्रतिरोध मार्च निकाला। समाहरणालय गेट पर पहुंचते ही सैकड़ों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के जंतर-मंतर और बिहार के विभिन्न हिस्सों में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए भर्ती प्रक्रिया में सुधार और समय पर परीक्षाएं कराने की मांग दोहराई।



असम बाढ़ पर पीएम मोदी ने की सीएम हिमंता से बात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से राज्य में व्याप्त बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री सरमा ने एक्स पर एक पोस्ट में बातचीत का विवरण साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बाढ़ की स्थिति, जलप्रलय से हुए नुकसान के पैमाने, राहत कार्यों की प्रगति और राज्य प्रशासन के सामने आने वाली चुनौतियों का जायजा लेने के लिए बुलाया था। मुख्यमंत्री के अनुसार, उन्होंने प्रधानमंत्री को असम सरकार की ओर से प्रभावित लोगों को राहत देने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी कि सहायता बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक पहुंचे। सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही दोहराया कि केंद्र इस संकट के दौरान असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि भारत सरकार इस आपदा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।



इंस्टा पर प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो

क्या इसे लोकतांत्रिक संस्कृति के नए अध्याय का आरंभ कहें

विनोद पाठक

भारतीय लोकतंत्र आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां राजनीति केवल विचारों, नारों और चुनावी सभाओं से नहीं, अपितु संचार के बदलते माध्यमों से भी आकार ले रही है। कभी समाचार पत्रों के संपादकीय, रेडियो संदेश, चुनावी रैलियां और टेलीविजन बहसें जनमत निर्माण के सबसे प्रभावी साधन मानी जाती थीं। आज वही भूमिका तेजी से मोबाइल स्क्रीन निभा रही है।

इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों ने राजनीति की भाषा, उसकी गति और जनता तक पहुंचने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, यह लोकतांत्रिक संस्कृति के नए अध्याय का आरंभ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं के लिए इंस्टाग्राम पर साझा किया गया एक सहज मोबाइल वीडियो कुछ ही समय में करोड़ों लोगों तक पहुंचा। इस घटना को केवल किसी लोकप्रिय सोशल मीडिया पोस्ट की सफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उस नए युग का संकेत है, जहां राजनीतिक नेतृत्व यह स्वीकार कर चुका है कि यदि नागरिक डिजिटल मंचों पर सक्रिय हैं तो लोकतांत्रिक संवाद को भी उसी भाषा और उसी माध्यम में विकसित होना होगा। यह परिवर्तन किसी एक राजनीतिक दल या नेता तक सीमित नहीं है। दुनिया के लगभग सभी बड़े लोकतंत्र अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

भारतीय राजनीति में डिजिटल संचार की यात्रा लगभग एक दशक पहले निर्णायक रूप से शुरू हुई। वर्ष 2014 के आम चुनावों ने पहली बार यह दिखाया कि सोशल मीडिया केवल प्रचार का सहायक माध्यम नहीं, अपितु चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ भी बन सकता है। ट्विटर, फेसबुक, 3डी रैलियां और डिजिटल अभियानों ने उस समय राजनीतिक संचार की नई दिशा निर्धारित की। इसके बाद सस्ते इंटरनेट, स्मार्टफोन की बढ़ती उपलब्धता और वीडियो-आधारित प्लेटफॉर्मों के विस्फोट ने राजनीति को पूरी तरह डिजिटल युग में पहुंचा दिया।

आज स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं को राजनीति और सरकार से जुड़ी पहली जानकारी किसी समाचार-पत्र या टेलीविजन चैनल से



नहीं, अपितु मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देने वाली एक छोटी-सी रील या वीडियो से मिलती है।

यही कारण है कि राजनीतिक संचार की शैली बदल गई है। पहले संदेश संस्थागत माध्यमों से प्रसारित होते थे। उनमें औपचारिकता अधिक होती थी। संवाद एकतरफा होता था। अब नेता सीधे कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ सेकंड में अपनी बात कहते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं और नागरिकों से तत्काल संवाद स्थापित करते हैं। इससे राजनीति पहले की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत दिखाई देने लगी है। नई पीढ़ी औपचारिक भाषणों की अपेक्षा ऐसे सहज संवाद से अधिक जुड़ाव महसूस करती है।

डिजिटल राजनीति का यह प्रभाव केवल चुनावी अभियानों तक सीमित नहीं है। जंतर-मंतर सहित देश के अनेक आंदोलनों ने यह सिद्ध किया है कि आधुनिक लोकतंत्र में हर नागरिक केवल प्रदर्शनकारी नहीं, अपितु संभावित संवादकर्ता भी है। पहले किसी आंदोलन की सफलता उसकी भीड़ और मीडिया कवरेज से आंकी जाती थी।

आज किसी भी प्रदर्शन का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसकी तस्वीरें, वीडियो और संदेश डिजिटल मंचों पर कितनी तेजी से फैलते हैं। एक साधारण मोबाइल फोन अब केवल संचार का उपकरण नहीं, अपितु जनमत निर्माण का माध्यम भी बन चुका है।

इस परिवर्तन ने लोकतंत्र को अधिक सहभागी बनाया है। अब किसी छोटे कस्बे की समस्या भी कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन सकती है। कई बार नागरिकों द्वारा साझा किए गए वीडियो प्रशासनिक कार्रवाई का आधार बनते हैं। सड़क दुर्घटनाओं से लेकर भ्रष्टाचार, पर्यावरण, महिला सुरक्षा, स्थानीय प्रशासन की लापरवाही जैसे अनेक मामलों में सोशल मीडिया ने जवाबदेही सुनिश्चित करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। इस अर्थ में डिजिटल मंचों ने नागरिक और शासन के बीच की दूरी कम की है।

लेकिन, हर परिवर्तन अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आता है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम सामान्यतः उसी सामग्री को अधिक प्रसारित करता है, जो भावनात्मक, विवादास्पद या सनसनीखेज हो। परिणामस्वरूप कई बार गंभीर नीतिगत चर्चाएं पीछे छूट जाती हैं और उत्तेजक सामग्री सार्वजनिक विमर्श पर हावी हो जाती है। राजनीति भी इस प्रवृत्ति से अछूती नहीं है।चुनावी बहसें कई बार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था जैसे मूल मुद्दों से हटकर वायरल वीडियो, ट्रेंडिंग हैशटैग और तात्कालिक विवादों तक सिमट जाती हैं। लोकतंत्र के लिए यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि लोकतांत्रिक निर्णय जितने अधिक तथ्यों पर आधारित होंगे, उनकी गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी।

हिरमगुंडा के जंगल से 6 नक्सल डंप बरामद



भारी मात्रा में आईईडी और विस्फोटक सामग्री जब्त

बीजापुर। 22 जुलाई 2026 को चलाए गए विशेष सर्च ऑपरेशन में हिरमगुंडा (पीडिया) के जंगलों से नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 6 डंप बरामद किए गए। इन डंपों से भारी मात्रा में आईईडी, विस्फोटक सामग्री और अन्य नक्सली उपयोग की वस्तुएं जब्त की गई हैं।

सूचना के आधार पर सीआरपीएफ रेंज बीजापुर के डीआईजी बी.एस। नेगी के निर्देशन और 199 वाहिनी के कमांडेंट आनंद कुमार, 85 वाहिनी के कमांडेंट सुनील कुमार राही और 202 कोबरा के कमांडेंट आलोक अवस्थी के मार्गदर्शन में संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व द्वितीय कमान अधिकारी विनोद कुमार ने किया।

ऑपरेशन में बी/199 कंपनी के सहायक कमांडेंट राजीव कुमार, ए/85 कंपनी के उप कमांडेंट टी। उमाकांत मितेई और बी/202 कोबरा के उप कमांडेंट कमलेश इंदौरा के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने पीडिया और मुतवंडी क्षेत्र के हिरमगुंडा जंगल में सघन तलाशी अभियान चलाया।

जवानों ने पूरी सतर्कता के साथ इलाके की घेराबंदी कर चरणबद्ध तरीके से सर्च ऑपरेशन संचालित किया। तलाशी के दौरान जंगल में छिपाकर रखे गए 6 अलग-अलग नक्सल डंप बरामद किए गए। इनमें नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से रखी गई आईईडी बनाने की सामग्री, कॉर्डेक्स वायर, डेटोनेटर, गन पाउडर, रेडियो सेट, विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिक सामग्री, नक्सली वर्दी और दैनिक उपयोग की वस्तुएं सहित कुल 30 प्रकार की सामग्री जब्त की गई। सीआरपीएफ ने कहा है कि 199 वाहिनी आम लोगों की सुरक्षा, क्षेत्र में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी सूचना आधारित अभियान और अधिक प्रभावी ढंग से जारी रहेंगे।

जिन सड़कों पर थीं कभी बारुदी सुरंग, अब बदल रहा तस्वीर



दंतेवाड़ा = कभी बारूदी सुरंग, बंदूकों की गोलियों और नक्सली हिंसा के कारण विकास से कोसों दूर रहे दक्षिण बस्तर के अंदरुनी इलाके आज तेजी से बदल रहे हैं। जिन क्षेत्रों में कभी सड़क बनाना असंभव माना जाता था, वहां अब बसें दौड़ रही हैं, एंबुलेंस पहुंच रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं और ग्रामीण विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन विकास, विश्वास और सुरक्षाझ की नीति पर लगातार काम करते हुए जिले के अंतिम छोर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में जुटे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के। बर्मन ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया कि करीब 15 वर्षों तक नक्सल हिंसा के कारण जिन क्षेत्रों में विकास नहीं पहुंच पाया था, वहां अब तेजी से सड़क, पुल-पुलिया, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और बस सेवाएं शुरू की जा रही हैं।इससे ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए जिला मुख्यालय नहीं आना पड़ता और अधिकांश सुविधाएं अब गांवों में ही उपलब्ध हो रही हैं।नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के बाद ग्रामीण खुलकर प्रशासन के पास अपनी जरूरतें और समस्याएं रख रहे हैं। प्रशासन भी उनकी मांगों के अनुरूप विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहा है।आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सलियों का भी पुनर्वास किया जा रहा है। उन्हें कौशल प्रशिक्षण, बैंक खाते, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।साथ ही रोजगार से जोड़ा जा रहा है। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के वे इलाके, जो कभी बारूदी सुरंगों और नक्सली हमलों के लिए बदनाम थे, आज विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।इन सड़कों पर नक्सली घात लगाकर हमला करते थे।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बड़ा बयान

कहा: धर्मेंद्र प्रधान को वापस लेना चाहिए इस्तीफा



दुर्ग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। भौगोलिकसंदर्भ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि एक विभाग में कई हजार कर्मचारी काम करते हैं।

ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति की गलती के लिए मंत्री को जिम्मेदार ठहराकर इस्तीफा मांगना उचित नहीं है। कोई भी मंत्री नहीं चाहेगा कि उसके विभाग में इस तरह से पेपर लीक हो। गजेंद्र यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। पुरानी मैकाले शिक्षा पद्धति में बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति (ह्श्वक्र) लाने में धर्मेंद्र प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वापस लिया जाना चाहिए।

चेरवापारा गौधाम में भूख-प्यास से परेशान गोवंश



कोरिया। जिले में सड़कों पर घूम रहे बेसहारा मवेशियों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया है। सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने हाल ही में विशेष अभियान शुरू किया है। कई निर्देश और आदेश के बाद भी ग्राम पंचायत चेरवापारा के रकेया स्थित गौधाम की जमीनी तस्वीर प्रशासन के दावों से बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। इस मुद्दे पर कलेक्टर रोक्तिमा यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय गौधाम समिति की बैठक हो चुकी है। जिसमें सभी गौधामों में चारा, पानी, शेड, पशुओं की स्वास्थ्य जांच, टैगिंग और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासन का दावा था कि गौधामों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और गोवंश के संरक्षण में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। स्थानीय लोगों और गौ सेवकों ने गौधाम की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि बिना किसी तैयारी के बड़ी संख्या में गोवंश को गौधाम में बंद कर दिया गया है, जहां उनके लिए न पर्याप्त चारा है, न पानी और न ही देखरेख की समुचित व्यवस्था। जानकारी के अनुसार करीब चार दिन पहले रात के समय ट्रैक्टरों के माध्यम से 100 से अधिक बेसहारा गायों और बैलों को इस गौधाम में लाकर रखा गया। आरोप है कि पशुओं को रखने से पहले न तो उनके भोजन की व्यवस्था की गई और न ही नियमित देखभाल के लिए कोई स्थायी कर्मचारी तैनात किया गया। किसी गोवंश की मौत होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी। यदि प्रशासन गोवंश को यहां रखता है तो पहले उनकी पूरी देखभाल सुनिश्चित करनी चाहिए।

ग्राम पंचायत गुल्लू की सरपंच पद से हटीं हर्षा साहू

नए सरपंच का जल्द होगा चुनाव



आरंग। जनपद पंचायत आरंग में आने वाली ग्राम पंचायत गुल्लू की सरपंच हर्षा चंद्रशेखर साहू के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हो गया। पीठासीन अधिकारी और आरंग तहसीलदार बाबूलाल कुर्रे की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न हुई। मतदान में 20 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 18 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और केवल 2 ने सरपंच के समर्थन में मतदान किया। इसके साथ ही महज डेढ़ साल के कार्यकाल में हर्षा साहू को सरपंच पद गंवाना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी बाबूलाल कुर्रे ने इसकी रिपोर्ट जनपद पंचायत और संबंधित अधिकारियों को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियमानुसार आगे पंचायत में नए सरपंच के चुनाव या वैकल्पिक व्यवस्था की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत के पंचों का आरोप है कि पंचायत में विकास कार्यों में अनियमितता, भ्रष्टाचार और मनमानी की जा रही थी। उनका कहना है कि महत्वपूर्ण फैसलों में पंचों की राय नहीं ली जाती थी और पंचायत के कामकाज में उनकी लगातार अनदेखी की जा रही थी। इससे लंबे समय से निर्वाचित प्रतिनिधियों में नाराजगी बनी हुई थी। पंचों ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत के शासकीय कार्यों में सरपंच पति चंद्रशेखर साहू का अनावश्यक हस्तक्षेप रहता था। उनका कहना है कि पंचायत के कई फैसलों पर सरपंच पति का प्रभाव दिखाई देता था, जिससे निर्वाचित पंच खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। इन्हीं कारणों से पंचों ने एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया और उसमें वे सफल भी हो गए।

चारामा में जलभराव की समस्या, व्यापारियों का फूटा गुस्सा

विधायक सावित्री मंडावी ने भी अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम



कांकेर। नेशनल हाईवे पर जलभराव की समस्या को लेकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। चारामा में लगातार हो रही बारिश से सड़क पर डेढ़ फीट तक पानी भर गया है जिससे दुकानदार परेशान हैं। पानी दुकानों और मकानों में घुस रहा है और कारोबार प्रभावित हो रहा है।

दुकानदारों के साथ स्कूली बच्चों, राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर विधायक सावित्री मंडावी और व्यापारियों ने प्रशासन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी गई है कि तय समय में समाधान नहीं हुआ तो नेशनल हाईवे-30 पर चक्काजाम किया जाएगा।

चारामा नगर में बारिश के दौरान नेशनल हाईवे-30 पर जलभराव की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि कुछ ही मिनटों की बारिश में सड़क पर करीब डेढ़ फीट तक पानी भर जाता है, जिससे सड़क पूरी तरह जलमग्न हो जाती है। इसका सीधा असर सड़क किनारे स्थित दुकानों और मकानों पर पड़ रहा है, जहां पानी घुसने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जलभराव के कारण ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पाते। व्यापारियों का आरोप है कि सड़क किनारे बनी नाली पर अतिक्रमण कर निर्माण कर दिया गया है, जिससे पानी की निकासी पूरी तरह बाधित हो गई है। उनका कहना है कि वे पिछले तीन वर्षों से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं और कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जलनिकासी की समस्या को लेकर विधायक सावित्री मंडावी व्यापारियों के साथ मौके पर पहुंचीं और नेशनल हाईवे-30 पर चक्काजाम की चेतावनी दी। सूचना मिलने पर चारामा तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से चर्चा की। बैठक के बाद प्रशासन को समस्या के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

व्यापारियों ने साफ कहा है कि यदि तय समय में जलनिकासी और अतिक्रमण की समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे नेशनल हाईवे-30 पर चक्काजाम कर आंदोलन करेंगे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बोरई बनेगा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं परिवहन का नया केंद्र

धमतरी। राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के समग्र विकास के लिए संचालित योजनाओं को धमतरी जिले में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने, आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराने तथा सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कमार समुदाय के लिए आधुनिक व्यवसायिक परिसरों (कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स) का निर्माण कराया जाएगा, ताकि वे स्वरोजगार स्थापित कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित इन व्यवसायिक परिसरों का निर्माण जिले के बेलरगांव, कसपुर, बोरई, कुकरेल, सिंगपुर, दुगली एवं केरेगांव में किया जाएगा। इन परिसरों में कमार समुदाय के हितग्राही अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार दुकानें संचालित कर सकेंगे। इससे उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

आईटीबीपी 53वीं वाहिनी ने महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया

बीजापुर। जिले के अबूझमाड़ के दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे ग्राम धुरबेड़ा से शनिवार सुबह भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 53वीं वाहिनी ने एक बार फिर मानवता और जनसेवा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, लगातार हो रही बारिश, उफनते नाले, घने जंगल और फिसलन भरे पहाड़ी रास्तों के बीच आईटीबीपी और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने सात माह की गर्भवती महिला को कई किलोमीटर तक पैदल चलकर सुरक्षित कर उसे सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार धुरबेड़ा निवासी 22 वर्षीय सुधा मांडवी, पति लालसू मांडवी, जो सात माह की गर्भवती हैं, को शनिवार सुबह अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। धुरबेड़ा जैसे सुदूर वनांचल क्षेत्र में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण परिजनों की चिंता बढ़ गई। इसी बीच आईटीबीपी 53वीं वाहिनी के अधिकारियों से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी गई । सेनानी संजय कुमार के मार्गदर्शन में आईटीबीपी ने तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू करने के निर्देश दिए।

प्राशा परधानपारा तोयनार के नवीन भवन का हुआ उद्घाटन

बीजापुर। जिले के नक्सल प्रभावित रहे इलाके के प्राथमिक शाला परधान पारा, तोयनार के नवीन भवन का उद्घाटन शनिवार को जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि इस शाला का पुन: संचालन शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रारंभ किया गया था। इससे पूर्व विद्यालय का संचालन अस्थायी शेड में किया जा रहा था। विद्यार्थियों की सुविधा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा नवीन शाला भवन का निर्माण कराया गया। नवीन भवन का उद्घाटन जिपं सदस्य, सरपंच, उपसरपंच खंड शिक्षा अधिकारी तथा वार्ड पंचों द्वारा फीता काटकर किया। इस अवसर पर ग्रामीणजन, संकुल शैक्षिक समन्वयक, प्रधान अध्यापक , प्रधान अध्यापक सहित विभिन्न शालाओं के शिक्षक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। उद्घाटन के पश्चात जिला पंचायत सदस्य मथियस कुजूर एवं खंड शिक्षा अधिकारी नागेश निषाद ने विद्यार्थियों के साथ कक्षा में सहभागिता करते हुए अध्यापन किया।

स्कूली बच्चों के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यशाला का आयोजन

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन मुख्यालय द्वारा स्कूली बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वयं को सक्षम बनाएं विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यशाला का आयोजन नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट सभागार में किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए व्यक्तित्व विकास, लक्ष्य निर्धारण एवं सकारात्मक सोच से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपने प्रेरक संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रत्येक बालक एवं बालिका में अद्वितीय प्रतिभा और असीम संभावनाएँ निहित होती हैं। आवश्यकता केवल अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निरंतर विकसित करने तथा आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर प्रदान करता है। ऐसे में प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी योग्यता को निरंतर निखारते हुए हर अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए।

महिला कर्मियों के लिए नई पहल कर रहा बीएसपी

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र में महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित के साथ-साथ अधिक जागरूक, आत्मविश्वासी और संवादपूर्ण बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संयंत्र के परियोजनाएं विभाग ने महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और जागरूकता को केंद्र में रखते हुए सखी संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह पहल केवल एक जागरूकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिला कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के लिए ऐसा साझा मंच है, जहां वे स्वास्थ्य, कार्यस्थल की चुनौतियों, सुरक्षा और व्यक्तिगत विकास से जुड़े विषयों पर खुलकर संवाद कर सकें। किया। कार्यक्रम में परियोजनाएं विभाग की महिला अधिकारी, महिला गैर-अधिशासी कर्मचारी तथा संविदा महिला कर्मियों सहित लगभग 30 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सहायक महाप्रबंधक ने कार्यस्थल पर प्रभावी संवाद और जागरूकता से जुड़े विषयों पर प्रस्तुति दी।

बुलेट में मानसून का मजा लेने निकले कलेक्टर व जिपं सीईओ



धमतरी। धमतरी जिले में पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने मानसून बाइक रैली निकाली। रुद्री चौक से शुरू हुई यह रैली गंगरेल होते हुए नरहरा जलप्रपात पहुंची। इस रैली की खास बात रही कि इसमें कलेक्टर, सीईओ और दूसरे विभागों के अधिकारी बाइक और दूसरी टू व्हीलर्स में नजर आए।

धमतरी जिला प्रशासन पर्यटन को बढ़ावा देने कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। बीते दिनों धमतरी के पर्यटनस्थलों की फोटो, रील और वीडियो बनाने का कॉम्पटीशन आयोजित किया, जिसकी आज आखिरी तारीख है। इस प्रतियोगिता में जीतने पर 50 हजार रुपये तक का इनाम रखा गया है। वहीं शुक्रवार को मानसून बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में जिला प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, बाइक राइडर्स, युवा और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। मानसून बाइक रैली में कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ भी बदले हुए अंदाज में नजर आए। अक्सर फॉर्मल ड्रेस में नजर आने वाले धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा जीन्स टीशर्ट में मॉडिफाइड बुलेट चलाते हुए नजर आए।

जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा भी कलरफुल टीशर्ट और जींस में बुलेट दौड़ा रहे थे। अधिकारियों कर्मचारियों की मानसून रैली का जगह जगह ग्रामीणों ने स्वागत किया। रैली के दौरान सभी बाइक सवारों ने हेलमेट पहनकर यातायात नियमों का पालन करने का भी संदेश दिया। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा ने नरहरा जलप्रपात का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, स्वच्छता और पर्यटक सुविधाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने बारिश के दौरान पर्यटकों की सुविधा के लिए शेड निर्माण के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि धमतरी के प्राकृतिक पर्यटन स्थल जिले की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने पर्यटकों से अपील की कि प्रतिबंधित और खतरनाक क्षेत्रों में न जाएं, प्लास्टिक और अन्य कचरा डस्टबिन में ही डालें और बच्चों के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतें। नरहरा जलप्रपात में अधिकारियों कर्मचारियों ने फोटो सेशन भी किया। कलेक्टर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। ग्रामीणों से बात की और नरहरा के आसपास के ग्रामीणों का आभार भी जताया। प्रशासन का कहना है कि ऐसे आयोजनों से जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सुरक्षित पर्यटन के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी।

जशपुर के शॉप से लाखों के मोबाइल चोरी का खुलासा

4 आरोपियों की गिरफ्तारी, 43 फोन बरामद



जशपुर। बगीचा थाना क्षेत्र में मोबाइल शॉप में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक बालिग और तीन विधि से संघर्षरत बालक शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 10 लाख रुपए कीमत के 47 मोबाइल, नकदी और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले में एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई 2026 की रात अज्ञात चोरों ने बगीचा बस स्टैंड प्रतीक्षालय के पीछे मौजूद कैपिटल मोबाइल शॉप का ताला तोड़ा।इसके बाद दुकान में रखे 93 नए और पुराने मोबाइल चोरी कर लिए। चोरी गए मोबाइल्स की अनुमानित कीमत करीब 18 लाख 75 हजार रुपए आंकी गई थी। दुकान संचालक जैद अली की शिकायत पर बगीचा थाना में अपराध क्रमांक 197/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 331(4), 305(ए) और 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए बगीचा पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अभिषेक प्रजापति सहित तीन विधि से संघर्षरत बालकों को हिरासत में लिया।

संक्षिप्त समाचार

राज्य मुख्य आयुक्त ने जिला संगठन आयुक्तों की बैठक में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

रायपुर। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स,



छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त श्री इंदरजीत सिंह खालसा की अध्यक्षता में जिला संगठन आयुक्तों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। राज्य मुख्य आयुक्त श्री खालसा ने सभी विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत का अनिवार्य रूप से गायन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संगठन के अंशदान की राशि 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से जमा कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में दल संचालन के लिए कम से कम एक बेसिक स्काउट मास्टर एवं एक गाइड कैप्टन प्रशिक्षित होना आवश्यक है। साथ ही राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले का भ्रमण कर स्काउट-गाइड गतिविधियों की समीक्षा किए जाने की जानकारी भी दी। उन्होंने ओवायएमएस पंजीयन कार्य को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक जिले में कार्यशाला आयोजित करने तथा प्रत्येक विकासखंड में एक-एक समन्वयक नियुक्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रत्येक जिला एवं विकासखंड स्तर पर वृहद वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने तथा उसमें समाज एवं जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

भाटापारा स्टेशन पर किलाबंदी टिकट चेकिंग के दौरान 212 मामला दर्ज

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ सुस्कर विपुल विलासराव के निर्देश पर भाटापारा रेलवे स्टेशन पर किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान 23 जुलाई को चलाया गया। जिसमें भाटापारा स्टेशन के सभी प्लेटफार्म, 08 ट्रेनों में किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान में कुल 212 मामलों को दर्ज कर 1,53,765 रुपए राजस्व प्राप्त किया गया। किलाबंदी टिकट चेकिंग में बिना टिकट यात्रा करने वाले 110 यात्री पकड़े गए, जिससे 98,665 राजस्व प्राप्त हुआ। अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वाले 66 यात्रियों से 51500 रूपये राजस्व प्राप्त हुआ, अधिक लगेज लेकर यात्रा करने वाले 36 यात्रियों से 3600 रूपये राजस्व प्राप्त हुआ । इस टिकट चेकिंग का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को टिकट लेने के प्रति जागरूक करना था। इस टिकट चेकिंग अभियान का संचालन सहायक वाणिज्य प्रबंधक अविनाश कुमार आनंद के द्वारा एवं मंडल मुख्य टिकट निरीक्षक ए. जेना, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक-टिकट चेकिंग अविजित डे सहित 12 टिकट चेकिंग स्टाफ, 04 आरपीएफ स्टाफ शामिल रहे रेल प्रशासन यात्रियों को आगाह करता है कि वे यात्रा हेतु उचित टिकट एवं रेल परिसर मे प्रवेश करने के पहले प्लेटफॉर्म टिकट अवश्य खरीदें। रेलगाड़ी एवं रेल परिसर को साफ सुथरा रखने में भी रेल प्रशासन को सहयोग प्रदान करें । रेलगाड़ी एवं रेल परिसर में गंदगी फैलाते पाए जाने पर 1000 रूपये से 5000 रूपये तक जुर्माना अथवा 06 महीने का कारावास का प्रावधान है ।

माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा दी गई राशि से 12 लोगों का होगा आँखों का ऑपरेशन

रायपुर। माहेश्वरी महिला संगठन के नवम सत्र के पदाधिकारियों द्वारा नेत्रदान महादान अभियान के तहत नवम सत्र की बची हुई राशि एक लाख पच्चीस हजार रूपयों को उदयाचल (राजनांदगांव) में दान किया गया। इस राशि से एक वर्ष में 12 लोगो के आंख का ऑपरेशन किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी कविता राठी ने बताया कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शशि गट्टानी के नेतृत्व में यह महादान किया गया जिससे किसी के जीवन से अंधकार मिटाया जा सके। वही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शशि गट्टानी ने बताया कि किसी के जीवन से अंधकार मिटाना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है और माहेश्वरी समाज हमेशा सेवा,त्याग और सदाचार के मार्ग पर चलते रहा है। इस अभियान की शुरूआत से पूरे प्रदेश के माहेश्वरी बंधुओं को जोड़कर और अधिक मानव सेवा करना ही संगठन का उद्देश्य है।

पीएम ने अपनी कुर्सी बचाने 'प्रधान' से मांगा इस्तीफा : दीपक बैज

रायपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर देशभर में सियासत तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक्स पर वीडियो जारी किया है। बैज ने कहा कि यह नैतिकता के आधार पर नहीं मजबूरी में दिया इस्तीफा है। युवाओं की एकजुट आवाज, लोकतांत्रिक संघर्ष और राहुल गांधी के लगातार समर्थन ने सत्ता को जवाबदेह बनने पर मजबूर कर दिया। यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं के संघर्ष की जीत है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने वीडियो में लिखा कि यह नैतिकता के आधार पर नहीं मजबूरी में दिया इस्तीफा है। और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के जंतर-मंतर समेत कई शहरों में प्रदर्शन चल रहा है। सरकार ने बात तक नहीं की, उलटा छात्रों पर बर्बतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। यह इस्तीफा इसलिए दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई। देश के युवाओं ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। लेकिन उनपर जो कार्रवाई हुई, उसको सदियों तक याद रखा जाएगा।

छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ की मांग

बस किराया बढ़ाओं नहीं तो 3 अगस्त को उग्र आंदोलन

रायपुर। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने डीजल के दामों में लगातार वृद्धि और यात्री किराए में की गई कटौती के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने साधारण बसों के किराए में 75 प्रतिशत और डिलक्स बसों के किराये में 30 प्रतिशत की वृद्धि की अधिसूचना तुरंत जारी करने के साथ ही महाराष्ट्र की तर्ज पर डीजल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के अनुसार किराया तय करने का स्थायी कानून बनाया जाए। मांग न मानने पर 3 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय के बस स्टैंडों पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि 14 अगस्त तक निर्णय नहीं लिया गया, तो पूरे छत्तीसगढ़ में अनिश्चितकालीन बस संचालन बंद कर दिया जाएगा।

महासंघ का आरोप है कि परिवहन विभाग ने 11 मार्च 2025 की अधिसूचना के तहत बस किराए में लगभग 25 प्रतिशत की कटौती कर दी है। विभाग ने इसके पीछे उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया था, जबकि न्यायालय



ने केवल चिल्हर की समस्या सुलझाने के लिए किराए को राउंड फिगर में तय करने का निर्देश दिया था। फिलहाल महासंघ आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। महासंघ का कहना है कि उच्च न्यायालय ने किराया कम करने का कोई आदेश नहीं दिया था लेकिन विभाग ने आदेश का त्रुटिपूर्ण अर्थ निकालकर किराए को घटा दिया, जिससे बस संचालकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

महासंघ ने बताया कि सितंबर 2021 के बाद से बीते 5 वर्षों में बसों के चेचिस, बॉडी निर्माण, डीजल, टायर, बीमा, स्पेयर पार्ट्स और चालक-परिचालकों के वेतन में भारी वृद्धि हो चुकी है। इसके साथ ही शासन द्वारा वीएलटीडी स्पीड गवर्नर, पैनिक बटन, रेडियम पट्टी और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जैसे सुरक्षा उपकरण अनिवार्य करने से बस संचालन का व्यवसाय काफी खर्चीला और अलाभप्रद हो गया है। वर्तमान में 90 प्रतिशत से अधिक बस संचालक आर्थिक तंगी से बदहाल हैं।

महासंघ के अनुसार 5 महीने पहले परिवहन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बावजूद कोई समाधान नहीं निकाला गया, जिससे निराश होकर बस संचालक अब गाडियां खड़ी करने पर मजबूर हो रहे हैं। महासंघ ने मांग रखी है कि 30 सितंबर 2021 के राजपत्र को आधार बनाकर साधारण बसों के किराए में 75 प्रतिशत और डिलक्स बसों के किराये में 30 प्रतिशत की वृद्धि की अधिसूचना तुरंत जारी की जाए। इसके अलावा महाराष्ट्र की तर्ज पर डीजल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के अनुसार किराया तय करने का स्थायी कानून बनाया जाए।

महासंघ ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि 31 जुलाई तक किराया वृद्धि नहीं की जाती है तो 3 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय के बस स्टैंडों पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि 14 अगस्त तक निर्णय नहीं लिया गया, तो पूरे छत्तीसगढ़ में अनिश्चितकालीन बस संचालन बंद कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी।

महाकालेश्वर मंदिर से गुढियारी रोड की दोनों तरफ की दुकानें टूटेंगी

रायपुर। पहाड़ीचौक-गुढियारी रोड को चौड़ी करके एक्सप्रेस-वे सड़क और स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7 की तरफ जोडने का काम लोक निर्माण विभाग कर रहा है। इस रोड के लिए पहले महाकालेश्वर मंदिर से गुढियारी रोड के एक तरफ के सभी 27 मकानों और दुकानों को पूरी तरह से तोडने की सर्वे सूची तैयार की गई थी। जबकि रोड के दूसरी तरफ नहीं तोड़ा जा रहा था। इसे लेकर लोगों में नाराजगी थी। इसे देखते हुए अब प्लान बदल दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के अनुसार अब दोनों तरफ तोडने का निर्णय लिया गया है। अभी यह रोड 10-15 फीट चौड़ी है। इसके सेंटर पाइंट के दोनों तरफ 33-33 फीट का दायरा टूटेगा। यही रोड गुढियारी बाजार के बाजू से होकर स्टेशन के प्लेटफार्म तरफ जुड़ेगी।

पश्चिम विधायक राजेश मूणत की पहल पर लोक निर्माण विभाग ने निर्माण समेत 84 करोड़ की स्वीकृति दी है। इसी राशि से महाकालेश्वर मंदिर



से गुढियारी बाजार तरफ जाने वाली सड़क के दोनों तरफ के 54 प्रभावितों के बीच मुआवजा बंटेगा। अभी रेलवे स्टेशन में री-डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कई गुना स्टेशन तक बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए पहाड़ी चौक की रोड को चौड़ी करने का प्लान बनाया गया है। इससे 12 से 14 वार्ड के लोगों को काफी सुविधा होगी। डिवीजन, एसडीओ, पीडब्ल्यूडी टीआर साहू ने कहा कि चौड़ीकरण के लिए महाकालेश्वर मंदिर से अब दोनों तरफ 33-33 फीट तोडने का निर्णय लिया गया है। इसकी सर्वे सूची बन गई है। दस्तावेजों की जांच के बाद मुआवजा दिया जाएगा।

12 जिलों में 795 सहायक शिक्षकों की होगी भर्ती

■ लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया विज्ञापन

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य की शासकीय शालाओं में सहायक शिक्षक (तृतीय श्रेणी, वेतन मैट्रिक्स लेवल-06) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। राज्य स्तर पर लोक शिक्षण संचालनालय ने ई एवं टी संवर्ग मिलाकर कुल 2,292 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें मैदानी क्षेत्रों के 12 जिलों में ई-संवर्ग के कुल 795 पद शामिल हैं। प्रमुख जिलों में दुर्ग (80), बिलासपुर (80), बलौदाबाजार (80), बेमेतरा (70) और रायपुर (70) शामिल हैं। इसके अलावा अन्य जिलों के लिए भी रिक्तियां निर्धारित



की गई हैं। आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए टी-संवर्ग के अंतर्गत 16 जिलों में कुल 1,497 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें जशपुर (150), बस्तर (125), बीजापुर (105), कांकेर (100) और कोण्डागांव (100) में सबसे अधिक रिक्तियां घोषित की गई हैं। इन जिलों में नियुक्ति के लिए भी व्यापमं के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विज्ञापन जारी होने के साथ ही डीएलएड एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों सहित शिक्षित बेरोजगार युवाओं में उत्साह का माहौल है।

सहायक शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2026 की स्थिति में 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा की संभावित तिथि 11 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। परीक्षा संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश, प्रवेश पत्र और अन्य जानकारी व्यापमं की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

दिसम्बर 2026 तक जिले को हर घर जल जिला बनाने के दिए निर्देश

रायपुर। कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्टर सभाकक्ष में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में शेष बचे ग्रामों की नलजल योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर बल दिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को दिसम्बर 2026 तक जिले को हर घर जल जिला बनाने की दिशा में कार्ययोजना बनाकर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।



समीक्षा के दौरान जिले के समस्त पेयजल स्रोतों, जिनका उपयोग नलजल योजनाओं में किया जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए रेन वाटर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर निर्माण की योजना एक सप्ताह के भीतर तैयार करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि रेन वाटर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर बनने से ग्रीष्म काल में जल स्रोतों का जलस्तर गिरने की समस्या से निजात मिलेगी और ग्रामीणों को गर्मियों में भी पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में नलजल योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां नए घरेलू नल कनेक्शन देने के लिए सर्वेक्षण किया जाए। इसके लिए प्रति उपअभियंता को 5 ग्राम तथा प्रति जिला समन्वयक को 5-5 ग्रामों का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने को कहा गया। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, ईई श्री अनिल बच्चन, सहित जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कवच प्रणाली का एसआईएल-4 ट्रायल सफल

रायपुर/बिलासपुर। भारतीय रेल की स्वदेशी अत्याधुनिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपूर रेल मण्डल के अंतर्गत कलमना-सालवा (25 किलोमीटर) रेलखंड में सायं 15ः00 बजे से 17ः30 बजे तक एसआईएल-4 स्तर का कवच ट्रायल ब्रेकिंग मोड ऑन में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस परीक्षण के दौरान कवच प्रणाली की विभिन्न सुरक्षा सुविधाओं का परीक्षण किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा।



परीक्षण के दौरान सिग्नल आस्पेक्ट की पहचान, स्वचालित ब्रेकिंग (ऑटोमैटिक ब्रेकिंग), स्वचालित गति नियंत्रण (ऑटोमैटिक स्पीड कंट्रोल) तथा आपातकालीन एसओएस प्रणाली (आपातकालीन अलर्ट) का परीक्षण किया गया और सभी परीक्षण संतोषजनक पाए गए। सामान्य परिस्थितियों में लाल सिग्नल मिलने पर लोको पायलट स्वयं ब्रेक लगाता है। यदि किसी कारणवश लोको पायलट समय पर ब्रेक लगाने में असमर्थ रहता है, तो कवच प्रणाली स्वतः सिग्नल की स्थिति का पता लगाकर स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देती है, जिससे ट्रेन सुरक्षित रूप से रुक जाती है और सिग्नल पास्ड एट डेंजर जैसी घटनाओं की संभावना को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है।

स्वचालित गति नियंत्रण परीक्षण के दौरान यह परखा गया कि रेलखंडों एवं यार्डों में निर्धारित गति प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित हो। यदि लोको पायलट निर्धारित सीमा के अनुरूप गति नियंत्रित नहीं कर पाता, तो कवच प्रणाली स्वतः हस्तक्षेप कर ट्रेन की गति को निर्धारित सीमा के भीतर ले आती है, जिससे संरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित होता है।

हॉट-लाइन तकनीक से चालू रेलवे ट्रैक के ऊपर खींची गई 220 केवी लाइन

■ राजधानी की बिजली व्यवस्था होगी और मजबूतत

रायपुर। राजधानी रायपुर की बिजली व्यवस्था को फुलप्रूफ बनाने के लिए दलदल सिवनी से रायता तक 220 केवी मल्टी सर्किट लाइन का कार्य हॉट-लाइन तकनीक से सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि लगभग 60 मीटर ऊंचे दो टावरों के बीच मुंबई-हावड़ा का अत्यंत व्यस्त रेलवे ट्रैक है, जहां औसतन हर 10 मिनट में एक ट्रेन गुजरती है। वहीं टावर के पास लगभग 12 फीट गहरा नाला भी है। ट्रांसमिशन कंपनी के अभियंताओं ने हॉट-लाइन तकनीक का उपयोग करते हुए रेलवे ट्रैफिक को बिना बाधित किए इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने इस महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि पर ट्रांसमिशन कंपनी के अभियंताओं एवं पूरी टीम को बधाई दी ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि दलदल सिवनी से रायता तक 220 केवी मल्टी सर्किट लाइन का कार्य तकनीकी दृष्टि से अत्यंत जटिल था। रेलवे ट्रैक को बिना



बाधित किए तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच हॉट-लाइन तकनीक से इस कार्य को पूरा करना ट्रांसमिशन कंपनी के अभियंताओं की तकनीकी दक्षता और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि दलदल सिवनी में निर्माणाधीन 220/132 केवी सब स्टेशन एवं इस लाइन सहित दोनों कार्यों पर लगभग 89 करोड़ रुपये की लागत आ रही है। इसके पूर्ण होने पर रायता स्थित 400 केवी सब स्टेशन से दलदल सिवनी 220/132 केवी सब स्टेशन तक सीधे बिजली पहुंच सकेगी तथा रायपुर में बिजली आपूर्ति के लिए पहले उपलब्ध 220 केवी की चार सर्किट लाइनें बढ़कर छह सर्किट लाइनें हो जाएंगी। लगभग 200 मीटर लंबे, मोटे एवं वजनी कंडक्टर को दूसरी ओर पहुंचाने के लिए पहले पायलट रोप तैयार किया गया। दोनों ओर पांच-पांच टन क्षमता की विंचिंग मशीनों का उपयोग किया गया। लगभग 90 डिग्री के कोण पर छह कंडक्टर (तार) खींचने में तीन दिन का समय लगा। 200 मीटर लंबे हिस्से को धीरे-धीरे खींचकर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया।

इस प्रकार रेलवे ट्रैफिक को बाधित किए बिना 220 केवी मल्टी सर्किट लाइन का कार्य पूर्ण किया गया। इस कार्य में डीआरएम कार्यालय के अधिकारी भी समन्वय बनाये रहे एवं ट्रैक पर सुरक्षा के इंतजाम के साथ निगरानी के लिये कर्मचारी तैनात किये गए थे। इस कार्य में कार्यपालक निदेशक श्री संजय पटेल, मुख्य अभियंता (परियोजना) श्री प्रसन्ना गोसावी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री ईश्वर कंवर, अधीक्षण अभियंता श्री वीए देशमुख, कार्यपालन अभियंता श्री यूके यादव, सहायक अभियंता श्री सुरेश वर्मा, श्री पीके तिवारी, श्री प्रबोल मिश्रा, श्री राम ठाकुर, श्री प्रतीक मित्रा तथा एजेंसी लक्ष्मी सिद्धार्थ ट्रांसमिशन के श्री वेणुगोपाल रेड्डी का विशेष योगदान रहा।

मोदी सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं : बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिस प्रकार से पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ आम जनता विरोध में है। छात्र नौजवान दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर देश के हर शहर में आंदोलन कर रहे है। यह बताता है कि सरकार जनता के विश्वास खो चुकी है। प्रधानमंत्री अपनी विफलता स्वीकार करें तथा तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। किसी प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ देश के युवाओं में ऐसा आक्रोश पहली बार देखने को मिल रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राजधानी रायपुर के नकटी से लेकर सरगुजा, बस्तर सभी जगह आम आदमी को बेदखल करने की कार्यवाही सरकार के द्वारा की जा रही है। सूरजपुर में कोयला खदान के लिए



ग्रामीणों को विस्थापित करने पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया वहां अप्रिय स्थिति निर्मित हुई। सूरजपुर, हसदेव, तमनार, छुईखदान बस्तर में आदिवासियों एवं आम लोगों की जल, जंगल, जमीन पर कब्जा करने दमनकारी कार्यवाही लगातार हो रही है। सूरजपुर जिला में जनता, भूमि अधिग्रहण में जमीन के बदले जमीन मांग रही है लेकिन सरकार उनका जमीन छीनकर पूंजीपतियो को देना चाहती है, बदले में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को जमीन नहीं देना चाहती है। ये जनता के साथ अन्याय है।सरकार किसी को विस्थापित करना चाहती है तो वहां के प्रभावितों को विश्वास में ले तथा उनका विस्थापन करे। डंडे के जोर पर विस्थापन अस्वीकार्य है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होता तो सबसे बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को होगा। यूसीसी छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के खिलाफ है, राज्य में केवल आदिवासी ही ऐसे है जिन्हें प्रदेश में निवासरत अन्य लोगों की अपेक्षा विशेष संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। इसके अलावा कोई भी वर्ग छत्तीसगढ़ में नहीं है जिसके लिए विशेष नागरिक प्रावधान लागू है। छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत से अधिक आबादी आदिवासियों की है, संरक्षित जनजातियां है, जिन्हें संविधान में कुछ विशेष अधिकार मिले है। उनकी रक्षा के लिए पेसा कानून लागू है और 5 अनुसूची लागू है और भाजपा यूसीसी लाकर आदिवासियों के हितों में डकैती डालने की कोशिश में है। बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा हुई है उसके बाद से ही भाजपा के समर्थित उद्योगपति बस्तर में आदिवासियों की जमीन पर नजरे गड़ाये हुए है। बस्तर में भाजपा के समर्थित उद्योगपतियों की नजर लग चुकी है और वह आदिवासियों की जमीन हड़पना चाहते है। यूसीसी लाने की कवायद इसीलिए है। राज्य के आदिवासियों के हितों को दरकिनार करके उद्योगपतियों के हितों को बढ़ावा देने की कोशिश है। आदिवासियों की जमीनें कानून दूसरा कोई ले नहीं सकता, इसलिए तमाम तरीके के रास्ते खोजने की शुरुआत की जा रही है।

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)

// मैनुअल ऑनलाईन प्रथम बार निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक-13 //

क्रमांक /584/NIT-13/व.ले.लि./ ग्रा.यां. सेवा/2026-27, सुकमा दिनांक- 23/07/2026

1. एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है:-

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू.लाख में)
1	2
प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य मोशलपारा, ग्रा.पंचा. गोंदपल्ली ।	14.51 लाख
नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य माटेमपारा, ग्रा.पंचा. गोंदपल्ली।	14.51 लाख
नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य सोफीरास, ग्रा.पंचा. गोंदपल्ली ।	14.51 लाख
नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य नाडीगुफा, ग्रा. पंचा. - रामाराम ।	14.51 लाख

निविदा डाऊनलोड एवं डी.डी. बनाने की अंतिम तिथि :- 03.08.2026

2. उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी विभागीय वेब साईट http://res.cg.gov.in से डाऊनलोड की जा सकती है।

कार्यपालन अभियन्ता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सुकमा
जिला - सुकमा (छ. ग.)

जी-262702356/5

मुद्दा विहीन आंदोलन समाप्त हो जाता है

पूरन चंद सरीन

आजादी से पहले और बाद में आंदोलन, हड़ताल, अनशन और धरना प्रदर्शन का लंबा इतिहास है। इनमें से अनेक देश या राष्ट्र भक्ति और जनसेवा के चोले में भ्रमजाल फैलाने और अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए वास्तविकता पर परदा डालने से अधिक न होने से बेअसर रहे। कच्चा चिट्ठा: दुनिया ने आंदोलन से शिक्षा सुधार, रोजगार सृजन, सामाजिक न्याय और आर्थिक मजबूती पाई और हमने नारे गढ़े और नेता पैदा किए जिसका परिणाम है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी एक ही सवाल पर अटके हैं : सड़क पर सबसे तेज आवाज किसकी है और सबसे पीछे कौन खड़ा है, गलाफाड़ नारे सबसे ऊंचे स्वर में कौन लगा सकता है! चाहे स्कूल, अस्पताल और रोजगार की लाइन सबसे लंबी हो। जिन्होंने आंदोलन से 'व्यवस्था' बदली, उन्हें याद रखा गया, जिन्होंने इससे 'पहचान' जोड़ी, वो वहीं रह गए। 80 साल में दुनिया में तीन सौ के लगभग बड़े आंदोलन हुए जिनमें से दो तिहाई सफल आंदोलन 'रोटी-कपड़ा-मकान-शिक्षा-रोजगार' पर हुए। बापू गांधी के बाद जॉर्ज फर्नांडीज की रेल हड़ताल, जे.पी. की समग्र क्रांति और अन्ना हजारे का व्यवस्था परिवर्तन उल्लेखनीय है। इनसे जो हासिल हुआ उसे सत्तालोभी नेताओं ने लील लिया और त्याग, बलिदान तथा उद्देश्यों पर काली स्याही फेर दी। हालांकि इनके असर से सरकार ने नए कानून बनाए लेकिन आधे अधूरे मन से लागू किए जैसे कि आरटीआई जो केवल जवाब देने तक सिमट गया, लोकपाल नियुक्ति करने पर रुक गया और किसान आंदोलन अधिकतर सही कृषि कानूनों को रद्द करवा कर समाप्त हो गया। सरकार से सीधी बात, लाठी से कंट्रोल में बदली, भीड़ वाली मानसिकता बढ़ी और मुद्दे वाले आंदोलन भी धमाचौकड़ी सिद्ध हुए। रोज बदलती मांग, गालियों का मंच और नेतागिरी चमकाने का मौक़ा सिर्फ़ सवाल उठाने, स्पष्ट न होने से हुड़दंग करने और जनता के लिए अपने दैनिक कामों में अड़चन से किसी की सहानुभूति न होने से आम जनता द्वारा भुला दिया गया। कड़वा सच है कि हमारा खुफिया तंत्र या तो इतना कमजोर है कि उसे कोई अनुमान नहीं होता कि किस घर में कौन सी खिचड़ी पक रही है और कौन कानून की धज्जियां उड़ाकर अव्यवस्था फैलाने की साजिश कर रहा है या फिर सरकार उसकी बातों को हवा हवाई कर रही है? इसके अतिरिक्त समय रहते पुलिस और प्रशासन तथा मंत्रिमंडल कोई कदम क्यों नहीं उठा पाते ताकि हालात बदतर न होने पाएं। जब चिडिया खेत चुग कर फुर्र हो जाती है तब इनकी आंख क्यों खुलती है ? इसका कारण यह है कि गृह मंत्रालय कुम्भकर्ण की नींद सोता है और तब ही जागता है जब शोर होता है और अराजकता फैल जाती है। जिम्मेदारी किसकी?: देश कोई मूर्ति नहीं बल्कि जीते जागते नागरिकों का सम्मान सहित जीवन है। शिकायती टट्टू नहीं, सुझाव या हल के साथ अपनी बात रखना ही परिणाम दिखाता है। आंदोलन से सरकार बदल सकती है लेकिन अनुशासन से देश बनता है। ऊल जलूल सवाल, अपने को कानून और मर्जी को विरासत समझने की आदत न गई तो जमाने को भूलने में वक्त नहीं लगता। समझना होगा कि आंदोलन लोकतंत्र का इंजन है जिस से गाड़ी चलती है और एक्सीडैंट भी होता है। वक्त का पहिया बहुत तेज़ी से घूमता है और संसार गवाह है कि धुरंधर और सर्वगुणसम्पन्न लेकिन अंदर से भयभीत नेतागण एक पल में गधे के सींग की तरह लुप्त हो जाते हैं। इसलिए जो हकीकत न समझे वह सबसे बड़ा अनाड़ी है और उसे अधिक खिलवाड़ करने से न रोका गया तो समझिए कि आधुनिक प्रलय निश्चित है जिसका वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं है लेकिन अटूट सत्य यही है। देश तब प्रथम होगा जब 140 करोड़ नागरिक प्रथम होंगे।

संवाद से सशक्त होगा लोकतंत्र, हिंसा से नहीं

ललित गर्ग

दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद भवन तक हाल के आंदोलन के दौरान जो तनाव, टकराव और हिंसक घटनाएं देखने को मिलीं, वे केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव, बैरिकेड तोड़ने के प्रयास, मेट्रो स्टेशन में जबरन प्रवेश की कोशिश, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग-ये सभी दृश्य उस लोकतांत्रिक संस्कृति के अनुरूप नहीं कहे जा सकते, जिसकी आधारशिला अहिंसा, संवाद और संवैधानिक मर्यादाओं पर रखी गई है। भारत आज आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 की ओर बढ़ रहा है। यह केवल आर्थिक महाशक्ति बनने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक परिपक्वता की कसौटी पर भी स्वयं को सिद्ध करने का अवसर है। यदि हम आज भी असहमति को हिंसा, टकराव और अराजकता के माध्यम से व्यक्त करेंगे, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होगी। लोकतंत्र की शक्ति सड़क पर शक्ति-प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विचारों की शक्ति, संवाद की संस्कृति और संवैधानिक प्रक्रियाओं में निहित होती है।

राहुल गांधी द्वारा नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर चल रहे घरना-प्रदर्शन के दौरान अचानक अपने सहयोगी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के निकट धरने पर बैठना और संसद की बजाय सड़क को राजनीतिक संघर्ष का मंच बनाना अनेक गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जिस प्रकार इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के तथाकथित छात्रों एवं कार्यकर्ताओं ने संसद चलो मार्च के दौरान तनावपूर्ण, अराजक एवं हिंसक माहौल बनाने की घटनाएं सामने आईं, उससे यह आशंका बलवती हुई कि कुछ राजनीतिक शक्तियां भारत में भी नेपाल जैसी अराजक परिस्थितियां पैदा करने को उजावले हैं। सरकार की सतर्कता और सुरक्षा एजेंसियों की समय रहते की गई कार्रवाई से, कुछ कमियों के बावजूद, इस बड़े संकट को टाल दिया गया, अन्यथा दिल्ली लंबे समय तक हिंसा और अशांति की चपेट में आ सकती थी। देश पहले भी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के दौरान शाहीन बाग में लगभग सौ दिनों तक एक प्रमुख सड़क के अवरुद्ध रहने और उससे आम नागरिकों को हुई भारी कठिनाइयों का अनुभव कर चुका है।



लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार निर्विवाद है, लेकिन उसका स्थान संसद, संवाद और संवैधानिक संस्थाएं हैं, न कि सड़क पर टकराव और अराजकता। विपक्ष यदि बार-बार ऐसे आंदोलनों को प्रोत्साहित करता है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि उसका उद्देश्य लोकतांत्रिक विमर्श को मजबूत करना है या राजनीतिक ध्रूवीकरण और अस्थिरता को बढ़ावा देना। जनता अपेक्षा करती है कि सभी दल संसद को सर्वोच्च मंच मानते हुए वहीं जवाबदेही सुनिश्चित करें।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण और निरस्त्र सभा करने का अधिकार देता है। यह अधिकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। किंतु प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य और मर्यादा भी जुड़ी होती है। प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस से टकराव करना, हिंसा फैलाना अथवा आम नागरिकों के जीवन को बाधित करना किसी भी दृष्टि से लोकतांत्रिक आचरण नहीं कहा जा सकता। यदि आंदोलन अपनी नैतिक शक्ति खो देता है, तो उसकी मांगें भी समाज की सहानुभूति खो बैठती हैं। यह भी उतना ही सत्य है कि लोकतंत्र केवल जनता के लिए नहीं, बल्कि सरकार के लिए भी उत्तरदायित्व का नाम है। सरकार को भी आंदोलनों को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर नहीं देखना चाहिए। जब भी किसी वर्ग, विशेषकर युवाओं और छात्रों में असंतोष उत्पन्न हो, तो उसका समय रहते समाधान खोजने का प्रयास होना चाहिए। संवाद के दरवाजे जितनी जल्दी खुलेंगे, टकराव की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी। लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य, संवेदनशीलता और संवाद की इच्छा होती है।

इतिहास साक्षी है कि भारत के अधिकांश सफल जनआंदोलन अहिंसा और संवाद की शक्ति से ही सफल हुए हैं। महात्मा गांधी ने विश्व को यह संदेश दिया कि सत्य और अहिंसा सबसे बड़े अस्त्र हैं। वर्ष 2011 का अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी इसका उदाहरण है। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन आंदोलन का नैतिक बल उसकी शांति और अनुशासन में था। उसी कारण सरकार को संवाद का रास्ता अपनाना पड़ा और पूरे देश में एक सकारात्मक बहस प्रारंभ हुई। इसके विपरीत जहां-जहां आंदोलनों ने हिंसा का मार्ग अपनाया, वहां उनका मूल उद्देश्य पीछे छूट गया और चर्चा केवल हिंसा तक सीमित होकर रह गई। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी कौन-सी शक्तियां हैं, जो सामान्य और भोली-भाली जनता एवं देश के युवाओं को हिंसा की ओर धकेल देती हैं? कौन-से तत्व आंदोलनों की दिशा बदलकर उन्हें अराजकता में परिवर्तित कर देते हैं? यह चिंता केवल सरकार की नहीं, पूरे समाज की होनी चाहिए। लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन यदि असहमति के मंच पर राष्ट्रविरोधी, अराजक अथवा हिंसक तत्व सक्रिय हो जाएं, तो उन्हें नियंत्रित करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनिवार्य दायित्व बन जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ अराजकता की स्वतंत्रता नहीं हो सकता।

संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। जंतर-मंतर लोकतांत्रिक विरोध का प्रतीक स्थल है। यदि इन दोनों के बीच हिंसा, तोड़फोड़ एवं अराजकता का दृश्य निर्मित होता है, तो यह केवल राजधानी की घटना नहीं रहती, बल्कि पूरे देश और विश्व के सामने भारतीय लोकतंत्र की छवि को प्रभावित करती है। लोकतंत्र की गरिमा इस बात में नहीं कि कौन अधिक आक्रामक है, बल्कि इस बात में है कि कौन अधिक संयमित और उत्तरदायी है। राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के दो पहिए हैं। यदि दोनों के बीच संवाद समाप्त हो जाएगा, तो लोकतंत्र टकराव का अखाड़ा बन जाएगा। विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, बल्कि रचनात्मक विकल्प प्रस्तुत करना भी है। उसी प्रकार सरकार का दायित्व केवल शक्ति प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि असहमति को सम्मानपूर्वक सुनना भी है। लोकतंत्र में किसी की पूर्ण विजय या पूर्ण पराजय नहीं होती, यहां अंतत: संवाद, सहमति और समाधान ही सबसे बड़ी जीत होती है।

छात्रों और युवाओं की समस्याओं का समाधान भी अत्यंत आवश्यक है। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा हैं। यदि उनकी आशाओं और अपेक्षाओं की उपेक्षा होगी, तो असंतोष स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह युवाओं से नियमित संवाद स्थापित करे, उनकी समस्याओं को समयबद्ध ढंग से सुने और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए।

वहीं युवाओं को भी यह समझना होगा कि हिंसा उनके आंदोलन की सबसे बड़ी शत्रु है। पत्थर और लाठी किसी समस्या का समाधान नहीं करते, वे केवल संवाद के पुलों को तोड़ते हैं। आज आवश्यकता लोकतंत्र को अधिक परिपक्व बनाने की है। हमें ऐसी राजनीतिक संस्कृति विकसित करनी होगी जिसमें विरोध हो, लेकिन वैमनस्य न हो। मतभेद हों, लेकिन मनभेद न हों। संघर्ष हो, लेकिन हिंसा न हो। लोकतंत्र में बहस जितनी प्रखर होगी, राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। किंतु बहस का स्थान यदि हिंसा ले लेगी, तो लोकतंत्र की आत्मा आहत होगी। जंतर-मंतर से संसद तक जो कुछ हुआ, उसे लोकतांत्रिक आदर्श नहीं कहा जा सकता। यह किसी परिपक्व राजनीतिक सोच का भी परिचायक नहीं है। राष्ट्र निर्माण का मार्ग टकराव नहीं, सहयोग है। हिंसा नहीं, सहमति है। उग्रता नहीं, उदारता है। इसलिए आवश्यक है कि सभी पक्ष अपने-अपने आग्रहों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें।

आज देश को ऐसे नेतृत्व और ऐसी जनचेतना की आवश्यकता है जो संवाद को संघर्ष से ऊपर रखे। सरकार उदारता और संवेदनशीलता दिखाए, आंदोलनकारी संयम और अनुशासन अपनाएं तथा राजनीतिक दल अल्पकालिक लाभ के बजाय लोकतंत्र की दीर्घकालिक मजबूती को प्राथमिकता दें। यही भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की वास्तविक पहचान भी है और भविष्य की आवश्यकता भी। अंतत: यही कामना की जानी चाहिए कि जिन शक्तियों के कारण आंदोलनों में हिंसा और टकराव का वातावरण बनता है, उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो। सभी पक्ष संवाद की मेज पर बैठें, अपनी बात तर्क, तथ्यों और संवैधानिक मर्यादाओं के साथ रखें तथा समाधान का मार्ग खोजें। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय किसी पक्ष की जीत नहीं होती, बल्कि वह क्षण होता है जब विरोधी पक्ष भी एक-दूसरे की बात सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही आदर्श लोकतंत्र की पहचान है और यही विकसित भारत की सबसे मजबूत बुनियाद भी है।

पुराण दिग्दर्शन ....



विश्व विद्या-निरुपणाध्याय: (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

सर्वसाधारण की कौन कहे भागवत के सैंकड़ों सप्ताह बाँच डालने वाले बड़े बड़े अद्वितीय (द्वितीय स्कन्ध के ज्ञान से शून्य) कथक्कड़ भी पञ्चमस्कन्धोक्त भूगोल की अर्थसङ्गति बिठलाने में गूंगे का गुड़ खा बैठते हैं। इसलिये हम सर्वप्रथम %पौराणिक भूगोल शैली और उसमें प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्दों का कुछ विवेचन करना आवश्यक समझते हैं ।

पौराणिक-भूगोल-शैली

(स्थूल और सूक्ष्म जगत् का तारतम्य)

हम इसी ग्रन्थ के शैलीवर्णनाध्याय में पुराणों की विशिष्ट शैली का निरूपण कर चुके हैं, तदनुसार श्री वेदव्यास जी ने जिस तरह ऐतिहासिक अंश के साथ 2 अन्यान्य वैज्ञानिक तत्त्वों को भी पुराण साहित्य में यत्र-तत्र विमिश्रित करके एक प्रघट्ट में ही अनेक उपयोगी रहस्यों को प्रकट कर डाला है, ठीक इसी तरह पौराणिक भूगोल प्रसङ्ग में भी स्थूल जगत् का यथावत् वर्णन करते हुवे साथ साथ सूक्ष्म किवा दिव्य जगत् का भी विशद निरूपण किया है। कहना न होगा कि भूमण्डल विषयक पौराणिक वर्णन को केवल इस प्रत्यक्षदृष्ट भूखण्डमात्र के साथ ही सम्बद्ध मानना पहली भूल हो सकती है।

वस्तुत: यह सब वर्णन जहाँ हमारी इस अकिञ्चन भूमि की संस्था का परिचायक है वहाँ इन्द्रियाक्रान्त एवं अनुभवैकवेद्य, सूक्ष्म जगत् के दिव्यसंस्थान का भी द्योतक है।

पौराणिक भूगोल-विद्या का मनन करते हुवे यह गुर कण्ठस्थ कर लेना चाहिये कि हमारा यह स्थूल जगत् इन्द्रियातीत सूक्ष्म जगत् का ही छोटा किन्तु सर्वाङ्गपूर्ण प्रतिबिम्ब (फोटो) है। सूक्ष्म जगत् में जिन 2 पदार्थों की जैसी स्थिति है हमारे इस स्थूल जगत् में भी उन 2 पदार्थों के प्रतिनिधिभूत पदार्थों की वैसी ही संस्था है।

क्रमश: ...

कारगिल विजय दिवस

योगेश कुमार गोयल

26 जुलाई को देश कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मनाएगा। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी फौज को बुरी तरह धूल चटाई थी। भारत-पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ वह युद्ध 60 दिनों तक चला था और पाकिस्तान फौज की करारी शिकस्त के बाद 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। पाकिस्तान पर भारत की इस जीत को याद करते हुए 26 जुलाई को 'कारगिल विजय दिवस' के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तानी सैनिकों और भाड़े के आतंकवादियों को मारकर या खदेड़कर कारगिल की चोटियों पर कब्जा करने के लिए चलाए गए 'ऑपरेशन विजय' के तहत तमाम बाधाओं को पार करते हुए



हमारे वीर जांबाजों ने उन्हें कारगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर जीत का परचम लहराया था लेकिन देश को इसकी बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। दरअसल उस युद्ध में भारत को विजय दिलाने में भारतीय सेना के सैंकड़ों जवान शहीद हुए थे। कारगिल युद्ध में न केवल भारतीय सेना के 527 सैनिक शहीद हुए थे बल्कि दो महीने तक चले उस युद्ध के दौरान 453 आम नागरिक भी मारे गए थे। इसीलिए भारतीय सेना की उस विजय के बाद सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 26 जुलाई को भारतीय सेना के शौर्य दिवस के रूप में कारगिल विजय दिवस मनाए जाने का फैसला लिया गया। सही मायनों में कारगिल विजय दिवस भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को स्मरण करने तथा उनके बलिदान को सम्मान देने का दिन है और 26 जुलाई का दिन विशेष रूप से देश के इन्हीं वीर सपूतों को समर्पित है। देश के जन-जन तक कारगिल युद्ध के इन्हीं नायकों के शौर्य और पराक्रम की गाथा पहुंचाने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। भारतीयवायु सेना भर्ती

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार कारगिल युद्ध हुआ था, जब दोनों देश सीधे तौर पर सैन्य संघर्ष में शामिल हुए थे। कारगिल युद्ध भारतीय सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों और कश्मीरी आतंकवादियों की घुसपैठ का ही परिणाम था। उस भीषण युद्ध में वायु शक्ति, तोपखाने और पैदल सेना के संचालन का व्यापक उपयोग किया गया था। युद्ध की खास बात यह थी कि वह युद्ध काफी ऊंचाई पर लड़ा गया था, जिसमें कुछ सैन्य चौकियां तो 18 हजार फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित थी। ऐसे में भारतीय सैनिकों के लिए वह लड़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण थी लेकिन हमारे जांबाजों ने देश की आन-बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहूति देकर न केवल पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाई बल्कि 700 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट भी उतारा। दुश्मन को रणनीतिक स्थानों से हटाने के लिए महत्वपूर्ण हवाई हमले करते हुए भारतीय वायुसेना ने उस युद्ध के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय सेना ने युद्ध के दौरान टोलोलिंग, टाइगर हिल, प्वाइंट 4875 सहित अन्य रणनीतिक चोटियों पर फिर से कब्जा कर लिया था। कारगिल युद्ध की शुरूआत 26 मई 1999 को भारतीय सेना के हवाई हमले के साथ हुई थी।

बिट्टू की एंट्री से बदली पंजाब की चुनावी बिसात

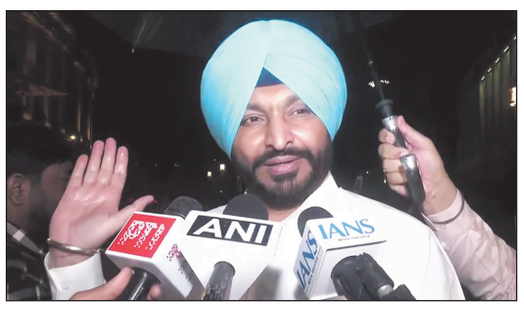
नीरज कुमार दुबे

केंद्रीय मंत्री पद से रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा पंजाब की राजनीति में भाजपा के सबसे बड़े चुनावी दांव के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बिट्टू विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और पार्टी के चुनाव अभियान का प्रमुख चेहरा भी बन सकते हैं। उल्लेखनीय है कि रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो चुका था। इसके बाद उन्होंने रेल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। बिट्टू ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें देश और विशेष रूप से पंजाब की सेवा करने का अवसर मिला तथा उनका सार्वजनिक जीवन राष्ट्रवाद, सेवा और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे भी जारी रहेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र बिट्टू लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। वर्ष 2009 में वह आनंदपुर साहिब से सांसद बने और बाद में दो बार लुधियाना का प्रतिनिधित्व किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का दामन थामा, लेकिन लुधियाना से कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ चुनाव हार गए। इसके बाद उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।

पंजाब की राजनीति में बिट्टू की वापसी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वह पिछले कुछ समय से पंजाब में भाजपा के संगठन और चुनावी तैयारी में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने पहले ही सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि भाजपा का लक्ष्य पंजाब में डबल इंजन सरकार बनाना है और प्रधानमंत्री मोदी के विकास के विजन को हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचाना है।

दरअसल, बिट्टू की वापसी भाजपा की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके तहत पार्टी पंजाब में अपने पारंपरिक शहरी हिंदू वोट बैंक से आगे बढ़कर सिख, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच भी मजबूत आधार तैयार करना चाहती है। पंजाब में लगभग 58 प्रतिशत आबादी सिखों की है, जबकि करीब 39 प्रतिशत हिंदू हैं। इसके अलावा राज्य में लगभग 32 प्रतिशत दलित और लगभग 16 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग है। भाजपा की कोशिश इन चारों सामाजिक वर्गों में समानांतर स्वीकार्यता बढ़ाने की है।



भाजपा की इसी नई रणनीति की झलक हाल में आई सतलुज फिल्म को लेकर हुए विवाद में भी देखने को मिली थी। रवनीत सिंह बिट्टू ने फिल्म का खुलकर विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह ऐसे संवेदनशील विषय को उभारने का प्रयास है, जिससे पंजाब का माहौल दोबारा तनावपूर्ण हो सकता है। उन्होंने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कोशिश बताते हुए फिल्म पर सवाल उठाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिट्टू का यह रुख भाजपा की बदली हुई चुनावी रणनीति का संकेत था। पहले जहां पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों पर अपेक्षाकृत आक्रामक भाषा का प्रयोग करती थी, वहीं अब वह सिख समुदाय की धार्मिक और ऐतिहासिक संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति को अधिक संतुलित और संयमित बना रही है। माना जा रहा है कि भाजपा पंजाब में सिख मतदाताओं के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए ऐसे मुद्दों पर सावधानीपूर्वक राजनीतिक संदेश देना चाहती है, ताकि हिंदू, सिख, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन चारों प्रमुख सामाजिक समूहों में समानांतर स्वीकार्यता विकसित की जा सके।

राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा ने स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बनने की दिशा में लगातार काम किया है। इसका असर चुनावी आंकड़ों में भी दिखा, जहां 2022 विधानसभा चुनाव में लगभग 6.6 प्रतिशत मत पाने वाली भाजपा का वोट प्रतिशत 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर लगभग 19 प्रतिशत तक पहुंच गया। यही कारण है कि पार्टी अब पंजाब में अकेले दम पर सत्ता हासिल करने का सपना देख रही है।

हालांकि शिरोमणि अकाली दल के साथ भाजपा के रिश्तों को लेकर राजनीतिक अटकलें अब भी खत्म नहीं हुई हैं। इसका ताजा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान देखने को मिला था। जालंधर की सभा में प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल तीनों पर निशाना साधते हुए कहा कि अकाली दल भी आपसी स्वार्थों के कारण पंजाब की प्रभावी सेवा नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री ने किसी विशेष अकाली गुट का नाम नहीं लिया, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बाद में दावा किया कि यह टिप्पणी उनकी पार्टी पर नहीं, बल्कि अन्य अकाली धड़ों के लिए थी। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी, क्योंकि भाजपा और अकाली दल का लगभग 25 वर्षों पुराना गठबंधन 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर टूटने के बाद भी दोनों दलों के हर सार्वजनिक बयान को संभावित राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जाता है। हालांकि भाजपा नेतृत्व फिलहाल गठबंधन पुनर्जीवित करने की किसी संभावना से इंकार कर रहा है और अपने संगठन को स्वतंत्र रूप से मजबूत करने की बात कह रहा है, फिर भी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब की राजनीति में भाजपा और अकाली दल के संबंध इतने महत्वपूर्ण रहे हैं कि दोनों दलों के बीच होने वाला हर संवाद भविष्य की संभावनाओं के नजरिए से परखा जाता है।

साथ ही भाजपा ने अपने राजनीतिक संदेश और भाषा में भी उल्लेखनीय बदलाव किया है। कभी ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाने वाली पार्टी अब सिख समाज की धार्मिक भावनाओं और ऐतिहासिक शिकायतों को अधिक संवेदनशीलता से संबोधित करती दिखाई दे रही है। पार्टी लगातार कांग्रेस को ऑपरेशन ब्लू स्टार, पंजाब में आतंकवाद के दौर और 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराती है, जबकि स्वयं को सिख समाज की भावनाओं का सम्मान करने वाली पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है।

देखा जाये तो भाजपा की इस बदली हुई राजनीतिक रणनीति की पृष्ठभूमि को समझने के लिए उसके पुराने रुख पर भी नजर डालना जरूरी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माय कंट्री, माय लाइफ में पंजाब में उग्रवाद के दौर के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों के लिए उग्रवाद को बढ़ावा दिया और हालात इतने बिगड़ने दिए कि अंतत: ऑपरेशन ब्लू स्टार की नौबत आ गई। आडवाणी ने यह भी लिखा था कि भाजपा और अन्य दलों के देशव्यापी आंदोलनों के दबाव में तत्कालीन केंद्र सरकार को स्वर्ण मंदिर परिसर से उग्रवादियों को हटाने के लिए सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी थी। हालांकि अब पंजाब में चुनावी विस्तार की कोशिशों के बीच भाजपा की सार्वजनिक भाषा पहले की तुलना में कहीं अधिक संतुलित और संवेदनशील दिखाई देती है। पार्टी अब ऑपरेशन ब्लू स्टार को राष्ट्रीय त्रासदी बताते हुए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन साथ ही सिख समाज की धार्मिक भावनाओं और ऐतिहासिक पीड़ा को भी प्रमुखता से स्वीकार करने का प्रयास कर रही है।

आज का इतिहास

1835 हवाई में पहला गन्ना बागान शुरू हुआ।
1858 बैरोन लियोनेल डे रोथस्चल्ड ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए पहले यहूदी व्यक्ति थे।
1882 बोअर भाड़े के सैनिकों ने ट्रांसवालिप रिपब्लिक से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और स्टेलैंडैंड गणराज्य की स्थापना की।
1936 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए कनाडाई अभियान बल के सदस्यों की स्मृति में समर्पित कनाडाई राष्ट्रीय विमि मेमोरियल, एक स्मारक स्थल वीमी, पास-डी-कैलास, को तहस-नहस कर दिया गया था।
1945 लेबर पार्टी ने 5 जुलाई को भूस्खलन से यूनाइटेड किंगडम का आम चुनाव जीता, जिसमें क्लीमेंट एटली के साथ विंस्टन चर्चिल को प्रधान मंत्री बनाया गया।
1951 नीदरलैंड ने जर्मनी के साथ युद्ध खत्म किया।
1953 एरिज़ोना में एक बहुसंख्यक मॉर्मन संप्रदाय पर शॉर्ट क्रीक छापा मारा गया।
1956 मिस्त्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया।
1965 मालदीव ब्रिटेन के अधीनता से स्वतंत्र हुआ।
1990 अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच। डब्ल्यू। बुश ने अमेरिकन्स डिसएबिलिटीज एक्ट, एक व्यापक नागरिक अधिकार कानून में हस्ताक्षर किए, जो कुछ परिस्थितियों में, विकलांगता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है।
1992 मैन ऑफ ला मंच 108 प्रदर्शनों के बाद मारकिस थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में बंद हो गया।
1998 एटीएंडटी और ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी पीएलसी ने संयुक्त उपक्रम बनाने की घोषणा की।
2005 नासा के अंतरिक्ष यान डिस्कवरी का प्रक्षेपण किया।
2007 पाकिस्तान ने परमाणु शक्ति सम्पन्न क्रूज मिसाइल बाबर हत्फ़-7 का सफल परीक्षण किया।
2008 यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर एक और नये ग्रह की खोज की।
2009 आतंकवादी इस्लामवादी संप्रदाय बोको हरम ने नाइजीरिया पुलिस बल स्टेशन पर हमला किया, जिसमें कई राज्यों में हिंसा भड़क उठी, नाइजीरिया में 1,000 से अधिक लोग मारे गए।
2010 अफगानिस्तान में युद्ध से संबंधित घटनाओं का विवरण देने वाले 92,000 से अधिक वर्गीकृत दस्तावेज़ विकिलिक्स द्वारा जारी किए गए हैं; यह अमेरिकी सैन्य इतिहास में सबसे बड़ा रिसाव है।
2011 वियतनाम ने प्रधान मंत्री गुयेन टैन डंग को फिर से चुना।

पंजाब में भाजपा मोदी के 5 सूत्री एजेंडे के तहत लड़ेगी विधानसभा चुनाव

इकबाल सिंह चन्नी

लगातार देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने और विशेष रूप से बंगाल के चुनावों में शानदार विजय हासिल करने के बाद भाजपा पंजाब का चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह आशान्वित है और इसके लिए एक बड़ी रणनीति बनाती नजर आ रही है। इसकी झलक भाजपा के बड़े नेताओं के दौरों से दिखाई दे रही है। पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह की मोगा रैली, जिसमें अमित शाह ने पंजाब में अगली सरकार बनाने पर पंजाब के लिए भाजपा के रोडमैप के बारे में बताकर पंजाबियों के दिल जीतने की कोशिश की। उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 3 दिवसीय दौरे के दौरान भाजपा के विभिन्न विभागों के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं से मुलाकात करके विधानसभा चुनावों में जीतने के लिए तैयारी करने का आह्वान किया।

और पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे ने पंजाब के प्रति भाजपा के एजैंडे को साफ कर दिया। मोदी ने जालंधर रैली में दिए गए भाषण में कहा कि पंजाब को भाजपा ही विकसित कर सकती है, पंजाब को आत्मनिर्भर भी भाजपा ही बना सकती है, निवेश भी भाजपा ही करवा सकती है और रोजगार के अलावा पंजाबियों द्वारा बनाए गए उत्पाद देश के कोने-कोने में पहुंचाने और उनकी बिक्री का प्रबंध भी भाजपा ही कर सकती है। प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में 5 बिंदुओं पर खास जोर दिया गया।

राजनीतिक एजैंडा : प्रधानमंत्री ने जालंधर की विकास रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ने का आरोप लगाते हुए भाजपा के 'कांग्रेस मुक्त भारत' के संकल्प को दोहराया। उन्होंने अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों ने उन्हें भी मौका देकर देख लिया है, वे भी कांग्रेस और 'आप' से अलग नहीं हैं। उनके इस बयान को पंजाब में भाजपा के अकेले चुनाव लडने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसी रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को 'कट्टर बेईमान पार्टी' करार देते हुए स्पष्ट संकेत दिया कि भाजपा के चुनाव अभियान का केंद्र आम आदमी पार्टी के नेताओं की कथित ईमानदारी के नकाब को



बेनकाब करना होगा।

सामाजिक समीकरण : प्रधानमंत्री के भाषण का दूसरा मुख्य बिंदू सामाजिक समीकरणों से जुड़ा था। उन्होंने शहीद तेजा सिंह समुंदरी को उनकी शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि देकर पंजाब के सामने भाजपा की पंथक सोच को भी उभारा। इसके अलावा उन्होंने गुरु रविदास जी के नाम पर अमृतसर से वाराणसी तक नई ट्रेन सेवा की शुरुआत की और सचखंड डेरा बल्लां के प्रमुख संत निरंजन दास के साथ रेल यात्रा के दौरान संक्षिप्त मुलाकात भी की। इसे दलित समुदाय के लिए स्पष्ट संदेश के रूप में देखा गया। पिछले 2 महीनों में संत निरंजन दास के साथ प्रधानमंत्री की यह दूसरी मुलाकात थी, जिसे पंजाब में भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा माना जा रहा है।

पंजाब की समस्याओं का समाधान : प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसानों, मनरेगा कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) देने का हवाला देते हुए उन्होंने किसानों के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही मनरेगा कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, पंजाब सरकार के कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते और अन्य लंबित मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि इनका प्रभावी समाधान सिर्फ भाजपा की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। उन्होंने आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रही और इससे राज्य के विकास में रुकावट पैदा हो रही है।

महिला सशक्तिकरण : प्रधानमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2027 के चुनावों से ठीक पहले महिलाओं को 1000-1500 रुपए देने का वादा करके उनके साथ धोखा किया। राजनीतिक हलकों में इसे इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा पंजाब की महिलाओं के लिए कोई बड़ी कल्याणकारी योजना या विशेष घोषणा कर सकती है।

अर्थव्यवस्था, कानून-व्यवस्था और विकास: प्रधानमंत्री ने राज्य की कमजोर अर्थव्यवस्था, बढ़ते कर्ज, विकास में पिछडने, गैंगस्टरवाद और नशे की समस्या का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को हल करने में अब तक की सभी सरकारें नाकाम रही हैं और अब पंजाब के सामने भाजपा ही एक विश्वसनीय विकल्प है। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में भाजपा की सरकार बनती है तो वह महाराजा रणजीत सिंह की 'सरकार-ए-खालसा' से प्रेरणा लेकर शासन करेगी, जहां खुशहाली, सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित किया जाएगा। पंजाब को सर्वोत्तम सुविधाएं देने में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना होगा, केंद्र की योजनाओं का पूरा लाभ लोगों तक पहुंचाना होगा, राज्य को कर्ज के बोझ से बाहर निकालना होगा और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना होगा। लुधियाना को साइकिल और हौजरी उद्योग का केंद्र, जालंधर को खेलकूद सामान उद्योग का हब और मोहाली को आई.टी. हब के रूप में विकसित करके रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। पंजाब में बने उत्पाद दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचेंगे औरराज्य फिर से आर्थिक रूप से मजबूती के साथ खड़ाहोगा।यह पांच सूत्री एजैंडा भाजपा के लिए कितना लाभदायक होगा, यह तो विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद ही पता चलेगा।

'उद्धव' और 'राज ठाकरे' के संयुक्त मार्च को लेकर गतिविधियां तेज

राहिल नोरा चोपड़ा

महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं क्योंकि शिवसेना (यू.बी.टी.) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे ने 26 जुलाई को एक संयुक्त मार्च निकालने की घोषणा की है, ताकि कॉकरोच जनता पार्टी (सी.जे.पी.) के विरोध मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई और नीट पेपर लीक विवाद को लेकर छात्रों और उनके अभिभावकों की चिंताओं को उजागर किया जा सके। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, ठाकरे चचेरे भाइयों ने कहा कि मार्च शिवाजी पार्क से शुरू होकर सिद्धिविनायक मंदिर पर समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि प्रतिभागी केवल राष्ट्रीय तिरंगा लेकर चलेंगे और छात्रों, अभिभावकों और सभी राजनीतिक विचारधाराओं के नागरिकों से रैली में शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की अपील की है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि केंद्र ने छात्रों के साथ बातचीत करने से इंकार करके आंदोलन को बढने दिया और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की आलोचना की।

पूरा 'इंडिया' छात्रों के साथ- राहुल : विपक्ष का विरोध परीक्षा पेपर लीक को लेकर तेज हो गया है, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने गांधी स्मृति में प्रदर्शन किया और पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी को उनकी प्रतिष्ठित सफेद टी-शर्ट में राष्ट्रीय ध्वज और संविधान पकड़े हुए देखा गया जबकि अन्य सांसद विरोध के प्रतीक के रूप में अपने मोबाइल फ्लैश लाइट जलाए और पेपर लीक तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाली तख्तियां लिए हुए थे। यह कहते हुए कि देश के छात्र अकेले नहीं हैं, राहुल ने कहा कि पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ मजबूती से खड़ा है और उनकी मांगों का समर्थन करता है। यह मार्च नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र और विपक्षी दलों के बीच चल रहे बड़े राजनीतिक टकराव के बीच आया है, एक ऐसा मुद्दा जिसने चल रहे मानसून सत्र के दौरान बार-बार संसद को बाधित किया है।

डिम्पल एक राजनेता के रूप में उभर रही : समाजवादी पार्टी (सपा) की लोकसभा सदस्य और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान आक्रामकता के साथ-साथ करुणा और साहस का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि वह वास्तव में एक राजनेता के रूप में उभर रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में डिंपल को पुलिस बैरिकेड्स पर चढने की कोशिश करते हुए और घायल छात्रों की मदद करते हुए दिखाया गया है, साथ ही संसद तक विरोध मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के दृश्य भी हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। वीडियो में डिम्पल को अपने एक पार्टी समर्थक से सड़क पर पड़े एक घायल युवक के लिए पानी लाने के लिए कहते हुए देखा गया और उन्होंने युवक की शर्ट का एक बटन खोलकर उसकी मदद की ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो। 16 जुलाई को, वह समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में जंतर-मंतर पर जलवायु कार्यकर्त्ता सोनम वांगचुक से मिलने के लिए लखनऊ से दिल्ली आईं, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त की थी। जंतर-मंतर पर डिंपल की मुखर उपस्थिति अब यह दर्शाती है कि समाजवादी पार्टी उन्हें एक बड़ी संगठनात्मक भूमिका के लिए तैयार कर रही है।

शरद पवार और सुले ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद) के भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ संबंधों को लेकर बार-बार अटकलों के बीच, पार्टी प्रमुख शरद पवार और उनकी बेटी एवं सांसद सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और महाराष्ट्र के कृषि संकट को उजागर करने वाला एक ज्ञापन सौंपा।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन: विरोध की भाषा या भाषा का पतन

विनोद पाठक

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह असहमति को स्थान देता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अपनी मांगों, शिकायतों और विचारों को शांतिपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने का अधिकार होता है। भारत में जंतर-मंतर लंबे समय से ऐसे जनांदोलनों का प्रतीक रहा है, जहां विभिन्न वर्ग अपनी समस्याओं को सरकार और समाज के सामने रखते रहे हैं। विरोध, प्रदर्शन और नारे लोकतंत्र की स्वाभाविक अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन इन सबके बीच संवाद की मर्यादा और भाषा का संयम भी उतना ही आवश्यक है।

अभी जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में जिस प्रकार की अभद्र, अश्लील और आक्रामक भाषा सुनाई दी, उसने केवल एक आंदोलन की शैली पर ही नहीं, अपितु हमारे सार्वजनिक विमर्श की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। किसी भी घटना का मूल्यांकन कुछ वीडियो के आधार पर पूरे समाज पर आरोप लगाकर नहीं किया जा सकता, फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि सार्वजनिक जीवन में भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है। चिंता केवल इस बात की नहीं है कि गालियां दी गईं, बल्कि इस बात की है कि उन्हें विरोध की वैध भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है।

भारत के छात्र और युवा आंदोलनों का इतिहास बताता है कि यहां विचारों की लड़ाई तर्क, संगठन और वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर लड़ी जाती रही है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आपातकाल के विरोध और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों तक अनेक आंदोलनों में युवाओं ने अपनी असहमति मुखरता से व्यक्त की, लेकिन लोकतांत्रिक संवाद की मर्यादा को महत्व दिया।

इसका अर्थ यह नहीं कि अतीत पूरी तरह आदर्श था, बल्कि यह कि प्रभावी विरोध के लिए अशिष्ट भाषा कभी अनिवार्य शर्त नहीं रही। आज सार्वजनिक जीवन में भाषा के बदलते स्वरूप के पीछे अनेक सामाजिक और तकनीकी कारण दिखाई देते हैं।

पहला कारण परिवारों की बदलती संरचना है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता ने परिवार के भीतर संवाद का समय कम कर दिया है। संयुक्त परिवारों के स्थान पर छोटे परिवार बढ़े हैं, माता-पिता पर कार्य का दबाव अधिक है और बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय पहले की तुलना में कम हो गया है।



यह कहना उचित नहीं होगा कि केवल परिवारों की संरचना बदलने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में संवाद, अनुशासन और व्यवहार संबंधी शिक्षा की भूमिका कमजोर हुई है।

दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षा व्यवस्था का है। आज विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ज्ञान और कौशल पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया जा रहा है, जबकि नागरिक उत्तरदायित्व, संवाद कौशल, संवैधानिक मूल्यों, नैतिक आचरण जैसे विषय अक्सर औपचारिकता तक सीमित रह जाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, अपितु जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी है।

यदि विद्यार्थी उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर लें, लेकिन मतभेद व्यक्त करने की सभ्य भाषा और लोकतांत्रिक संस्कार विकसित न कर सकें तो शिक्षा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। भारतीय परंपरा में %विद्या ददाति विनयम% केवल एक सूक्ति नहीं, बल्कि शिक्षा का मूल दर्शन रहा है। ज्ञान के साथ विनम्रता, असहमति के साथ संयम और अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध, यही शिक्षा की वास्तविक कसौटी है।

डिजिटल क्रांति ने भारतीय समाज को अभूतपूर्व अवसर दिए हैं। इंटरनेट ने शिक्षा, सूचना और अभिव्यक्ति के नए द्वार खोले हैं, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया मंचों की एल्गोरिदमिक संरचना अक्सर उत्तेजक, विवादास्पद और आक्रामक सामग्री को अधिक दृश्यता देती है। ऐसे वातावरण में संयमित और तथ्यपरक संवाद की अपेक्षा तीखी भाषा अधिक तेजी से फैलती है।

परिणामस्वरूप कई बार युवा यह मानने लगते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए आक्रामक भाषा आवश्यक है। मनोरंजन उद्योग और डिजिटल सामग्री का प्रभाव भी इस विमर्श का हिस्सा है। फिल्मों, वेब सीरीज, स्टैंड-अप कॉमेडी और सोशल मीडिया कंटेंट में अभद्र भाषा का प्रयोग पहले की तुलना में अधिक सामान्य दिखाई देता है।

यह कहना उचित नहीं होगा कि केवल यही कारण है, लेकिन यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि लोकप्रिय संस्कृति समाज की भाषायी आदतों को प्रभावित करती है। विशेष रूप से किशोर और युवा वर्ग अपने पसंदीदा कलाकारों, कंटेंट क्रिएटर्स व प्रभावशाली व्यक्तियों की भाषा और व्यवहार से प्रभावित होता है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी उतना ही आवश्यक है।

लोकतंत्र में असहमति का अधिकार मौलिक है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यही संविधान सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और दूसरों की गरिमा का सम्मान करने की भी अपेक्षा करता है।

विरोध तब अधिक प्रभावी होता है, जब वह तथ्यों, तर्कों और नैतिक बल पर आधारित हो। यदि संवाद का स्थान अपमान, गाली और व्यक्तिगत आक्षेप ले लें, तो अंततः लोकतांत्रिक संस्कृति ही कमजोर होती है। इस समस्या का समाधान केवल कानूनों से नहीं निकलेगा।

सबसे पहले परिवारों में संवाद की संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा। बच्चों के साथ समय बिताना, उनकी डिजिटल गतिविधियों में रुचि लेना और उन्हें भाषा तथा व्यवहार की मर्यादा सिखाना अभिभावकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विद्यालयों व विश्वविद्यालयों को भी संवाद कौशल, नागरिक शास्त्र, संवैधानिक मूल्यों और डिजिटल नागरिकता को शिक्षा का प्रभावी हिस्सा बनाना होगा।

सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल मंचों पर आयु-आधारित सुरक्षा उपायों, प्रभावी कंटेंट मॉडरेशन, पारदर्शी नियामक व्यवस्था और मौजूदा कानूनों के निष्पक्ष क्रियान्वयन को मजबूत किया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि अनावश्यक प्रतिबंधों के बजाय जवाबदेही की संस्कृति विकसित हो।

मनोरंजन उद्योग, सोशल मीडिया मंचों और प्रभावशाली डिजिटल रचनाकारों को भी यह समझना होगा कि उनका प्रभाव करोड़ों युवाओं तक पहुंचता है। लोकप्रियता के लिए अभद्रता का सहारा लेना अल्पकालिक लाभ दे सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह सामाजिक संवाद को नुकसान पहुंचाता है।

डोनाल्ड ट्रम्प का रुख भारत से सहयोग का नहीं

राजेश बादल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मानो भारत के विरुद्ध अघोषित जंग छेड़ दी है। यह जंग हथियारों और फौज-फाटे के दम पर नहीं लड़ी जा रही है। स्पष्ट है कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक कारोबारी महाशक्ति बनने से रोकने के लिए यह जंग छेड़ी जा रही है और इस मामले में चीन उसका साथ दे रहा है। रूस और भारत के विरुद्ध चीनअमेरिका को अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति का यह रवैया हिंदुस्तान के लिए चेतावनी भरा संदेश है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विसर्जित होने के बाद से अब भारत को निर्णायक नीति पर काम करना आवश्यक है। भारतीय विदेश नीति के शिल्पी अपने लिए इसे संकट की घड़ी मान सकते हैं क्योंकि उनके पास विकल्प सीमित हैं। जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसे पड़ोसी शत्रु देशों की तरह व्यवहार करने लगें तो रूस, ईरान, अफगानिस्तान और भूटान जैसे मित्र राष्ट्रों के साथ अपने रिश्तों में गहराई और भरोसा बनाए रखना जरूरत बन जाता है।

डोनाल्ड ट्रम्प की नई घोषणा भारतीय दवाओं पर 200 प्रतिशत आयात कर लगाने के बारे में है। जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान के कुल अमेरिकी निर्यात में लगभग 40 फीसदी दवाएं होती हैं। औसतन हर तीसरे अमेरिकी घर में जीवन उपयोगी भारतीय दवाएं उपयोग में ली जाती हैं। दो सौ प्रतिशत आयात शुल्क करने का अर्थ यह है कि आम अमेरिकी अवाम पर दवा का बोझ बेहद बढ़ जाएगा, जबकि उनकी आमदनी जस की तस है। इलाज भी वहां पहले ही बहुत महंगा है। ऐसे में महंगी चिकित्सा से उनकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता। कुछ समय बाद अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं और ट्रम्प को इनमें करारा झटका लगने वाला है, यह छिपा हुआ तथ्य नहीं है। लेकिन जब भारत को नुकसान पहुंचाने की मंशा हो तो ट्रम्प शायद यह झटका स्वीकार करने के लिए भी तैयार होंगे।

ट्रम्प प्रशासन यह तर्क दे रहा है कि दवा कंपनियां



अमेरिका में ही जीवनोपयोगी दवाओं का निर्माण करें। पर, यह व्यावहारिक रूप से असंभव दिखता है। अमेरिका के कानून को देखते हुए दवा उत्पादन की एक नई इकाई लगाना वहां टेढ़ी खीर है। यहां तक कि अमेरिका अपने मुल्क के लिए शून्य विक्रयकर कर दे (जो कि संभव नहीं है) तो भी भारतीय दवाओं से वे सस्ती नहीं होंगी। एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा कि अमेरिका में मानव श्रम भारत की तुलना में कई गुना महंगा है। सिर्फ इसी वजह से लागत मूल्य बढ़ जाएगा। इसके अलावा संसार में दवाओं के लिए रॉ मटेरियल चीन और भारत में सर्वाधिक मिलता है। चीन से भारत लाने में ट्रांसपोर्ट शुल्क न्यून है, जबकि अमेरिका के लिए चीन और भारत से रॉ मटेरियल आयात करना अपेक्षाकृत महंगा होगा।

जाहिर है कि अपनी भारत विरोधी सनक के चलते ट्रम्प इस तरह के फैसले ले रहे हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका में अवैध प्रवासियों के संदर्भ में भारत को धरती का नरक बताया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए सख्त विरोध दर्ज कराया था। ईरान और रूस से कच्चे तेल की खरीद पर तो वह पहले ही अपनी नाराजगी प्रदर्शित कर चुका है। अमेरिका की यह विचित्र धौंस है कि डेढ़ सौ करोड़ की आबादी वाला राष्ट्र अपनी मर्जी से ईंधन भी खरीद नहीं सकता। इसके अलावा वे एच-1 बी वीजा नियमों को और सख्त बनाए जाने पर जोर दे चुके हैं। इसका असर सीधे-सीधे भारतीय पेशेवरों पर होने वाला है। यह अलग बात है कि भारतीय पेशेवरों के बिना अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री लगभग ठप हो जाएगी।

इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों ने हमको तब तक लूटा, जब तक हम चुप रहे। जैसे ही भारत ने गोरी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें देश से जाना पड़ा। क्या अमेरिका भारतीय नक्शे में अपनी कारोबारी उपस्थिति का सफाया चाहता है ? चंद रोज पहले अमेरिका ने ईरान में भारत की ओर से बनाए गए चाबहार बंदरगाह को हमले में नष्ट कर दिया। ईरान में इस बंदरगाह के लिए भारत पांच दशकों से प्रयास कर रहा था। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बनाया। दोनों मुल्कों का मकसद उससे भारत को घेरना है। गुजरात प्रदेश ग्वादर से करीब है। इसलिए ग्वादर के पीछे ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाने में भारत की मंशा घेराबंदी की रणनीति को नाकाम करने की थी, लेकिन चाबहार पर हमले से भारत को रणनीतिक रूप से भारी क्षति हुई है। व्यापार चटक गया, सो अलग। हिंदुस्तान की तरफ से इसका तीव्र प्रतिरोध आवश्यक था। डोनाल्ड ट्रम्प के दबाव में संसार का सबसे पुराना और एक विराट देश क्यों आए? चाबहार को क्षति से स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका एशिया में पाकिस्तान और चीन के साथ गठजोड़ का एक नया संस्करण तैयार करना चाहता है।

वह भारत, रूस, अफगानिस्तान और ईरान जैसे राष्ट्रों को रिश्ते की एक डोर में बंधा नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान तो आधी सदी से उसकी गोद में बैठा हुआ है और अमेरिका भारत के विरोध में जब-तब उसका इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक ऐसा बच्चा है ,जिसे वह कभी-कभार लॉलीपॉप देकर संतुष्ट कर देता है। अब ईरान के साथ मध्यस्थता कराने के नाम पर (जो नाकाम रही है) पाकिस्तान ने अमेरिका से 96000 करोड़ रुपए की भीख मांगी है। अमेरिका उसकी मदद कर भी देगा, क्योंकि उसका अघोषित सैनिक अड्डा पाकिस्तान में चलता रहेगा। इमरान खान इसके विरोधी थे इसलिए उन्हें सत्ता से हटवाया गया। बांग्लादेश में भी अमेरिका ने यही किया। अब भारत उसके निशाने पर है।

सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार और टिप्पणी

सनत जैन

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च के दौरान छात्रों पर हुई लाठी चार्ज, आंसू गैस और पुलिस का दुर्व्यवहार, आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने के मामले की त्वरित सुनवाई से इंकार कर दिया था। तीन जजों की बेंच के सामने यह याचिका लगाई गई थी। याचिकाकर्ता वकील से मुख्य न्यायाधीश ने कहा, उनकी इस याचिका और आप जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हमें कोई रुचि नहीं है। जब वकील साहब ने दूसरी बार अनुरोध किया तो मुख्य न्यायाधीश ने नाराजी के साथ कहा, हमारा और अपना समय बर्बाद मत करें। मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी की देश भर में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। इससे पहले एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच शब्द का उपयोग किया था। उनका कहना था कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं। उसके बाद इस पर बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और विदेश में कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया। आज वही सीजेपी जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रही। संसद मार्च के दौरान पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया, सैकड़ो छात्र पुलिस लाठी चार्ज में बुरी तरह घायल हुए, प्रदर्शनकारियों के ऊपर पेलट गन एवं इलेक्ट्रिक छड़ी का इस्तेमाल किया गया। सादी वर्दी वाली पुलिस ने कई घंटे तक जबरदस्त मारपीट की। घायलों का इलाज नहीं हुआ। सैकड़ो लोगों को हिरासत में लेकर वहां से ले जाया गया। पुलिस ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की। अधिकांश प्रदर्शनकारियों के पास मोबाइल फोन थे, जो प्रदर्शन स्थल और जंतर मंतर में हर घटना का वीडियो बना रहे थे, कई वीडियो का लाइव प्रसारण हो रहा था, उसमें दिल्ली पुलिस की अमानवीय और अवैधानिक कृत्य इंटरनेट के जरिए सारी दुनिया देख रही थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी स्वयं याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस संवेदनशील घटना पर जहां सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना था वहां पर याचिका पेश होने के बाद यह कहना कि हमारा समय बर्बाद ना करें, वीडियो पर हमारी कोई रुचि नहीं है, याचिका की सुनवाई अभी नही होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जिस तरह से सरकार के पक्ष में निर्णय हो रहे हैं अदालतों से सरकार को एक तरह से संरक्षण दिया जा रहा है उसकी प्रतिक्रिया अब पूरे देश में हो रही है। इसके साथ-साथ अब यह चर्चा भी चल पड़ी है जज भगवान नहीं हैं, उन्हें भी नियम कानून और संविधान के तहत काम करना होता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका का है। न्यायपालिका का अस्तित्व केवल जजों से नहीं होता है। अधिवक्ता और बार काउंसिल भी न्यायपालिका के प्रमुख अंग हैं। यदि न्यायपालिका में जज की कुर्सी पर बैठे न्यायाधीश यदि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में बार काउंसिल और अधिवक्ताओं को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आना होगा। न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष और प्रभावी बनाए रखने की जिम्मेदारी इन तीनों पक्षों की है। अधिवक्ताओं का पंजीकरण बार काउंसिल में होता है जब कोई जज बन जाता है तब उसका पंजीकरण बर काउंसिल से स्थगित कर दिया जाता है। बार काउंसिल अधिवक्ताओं पर अनुशासन, पेशेवर आचरण, न्यायपालिका की सुचिता और अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करता है। जो अधिवक्ता न्यायाधीश बन जाते हैं यदि वह अपने आचरण का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, उनके निर्णय दोषपूर्ण हैं, ऐसी स्थिति में प्रदेश के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शिकायत की जा सकती है। यदि मुख्य न्यायाधीश भी उसकी आंतरिक जांच नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं, ऐसी स्थिति में बार काउंसिल और अधिवक्ता जो फैसला जजों द्वारा किए गए हैं और उनमें जो गड़बड़ी हैं उसको लेकर अपील पुनर्विचार और पुनरीक्षण याचिका लेकर जो दोषपूर्ण फैसलें हैं याचिका के माध्यम से उचित न्याय की मांग कर सकते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में बार काउंसिल, अधिवक्ता और जजों की भूमिका स्पष्ट है। तीनों न्यायपालिका की संपूर्ण अवधारणा के परिचायक हैं और तीनों की ही जिम्मेदारी है संविधान और नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना। न्यायपालिका की संवैधानिक जिम्मेदारी है लेकिन जिस तरह से नागरिकों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं और जांच एजेंसियां जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, सरकार जो कानून बना रही है उसमें संवैधानिक एवं मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर टाले अकाल मृत्यु और दिलाए मोक्ष



दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग- शंकर जी का यह अनोखा मंदिर अन्य प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में एक मात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि दक्षिण दिशा के स्वामी स्वयं भगवान यमराज हैं। तभी जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आ कर भगवान शिव की सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे मृत्यु उपरांत यमराज द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से मुक्ति मिलती है।

अकाल मृत्यु टालते हैं शिव जी-देश-दुनिया से काफी लोग यहां पर इसलिये भी दर्शन करने आते हैं कि जिससे वे अपनी अकाल मृत्यु को टाल सकें और सीधे मोक्ष को प्राप्त कर सकें।

सारी इच्छा करते हैं पूरी- भगवान शिव अपने भक्त की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अगर आपको अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है तो यहां आ कर एक बार दर्शन जरुर करें, जिससे आपको धन, धान्य, निरोगी शरीर, लंबी आयु, संतान आदि सब कुछ प्राप्त हो।

पृथ्वी का केंद्र हैं महाकाल- कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु है और संपूर्ण पृथ्वी के राजा भगवान महाकाल यहीं से पृथ्वी का भरण-पोषण करते हैं।

गाय के कंडे से होती है भस्मार्ती-यहाँ पहले महाकाल की भस्म आरती में ताजा मुर्दे की भस्म का ही प्रयोग होता था, किन्तु महात्मा गांधी के आग्रह के पश्चात शास्त्रीय विधि से निर्मित उपल-भस्म से भस्मार्ती होने लगी।

हनुमान जी के गुणों से आलोकित करें जीवन

मनोजवं मारुत तुल्यवेगंए जितेन्द्रियं बुद्धिमना वरिष्ठम।
वातात्मजं वानरयूथ मुयंएश्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये॥



यदि हम खुद को हनुमान जी का सच्चा भक्त मानते हैं, तो हमें ऐसे महान चरित्र के चारित्रिक गुणों के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करने का प्रयास करना चाहिए।

उक्त श्लोक द्वारा हमें सर्वतोमुखी शक्ति के प्रतीक हनुमान जी का यथार्थ चित्रण मिलता है की कैसे वे शरीर के साथ-साथ मन से भी अपार बलशाली थे एवं उन्होंने वासना को जीत लिया था। वे जितेन्द्रिय थे और बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठतम थे। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भारत के लोगों के मन में हनुमान जी का चरित्र उनकी ईश्वर भक्ति, ईश्वर सेवा और ईश्वर के प्रति वफादारी के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसलिए ही यहां के अधिकतर घरों में उनकी मूर्ति प्रतिदिन पूजी जाती है और देश के कोन-कोने में भी उनके अनगिनत मंदिर बने हुए हैं। जन के दिलों में स्थान पाने वाले हनुमान जी की पूजा-अर्चना करना उनके प्रति हमारी श्रद्धा का एक पहलू है, लेकिन उनके चारित्रिक गुणों से प्रेरणा लेना व उनके गुणों को जीवन में आत्मसात करना सर्वथा दूसरा पहलू है।

अत: यदि हम खुद को हनुमान जी का सच्चा भक्त मानते हैं, तो हमें ऐसे महान चरित्र के चारित्रिक गुणों के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करने का प्रयास करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन जन्मे हनुमान जी के यूं तो अनेक नाम हैं, परन्तु सर्वाधिक प्रचलित हनुमान शद का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो मान का हनन करने वाला हो। पौराणिक कथाकारों के अनुसार ज्ञानसूर्य परमात्मा के ज्ञान गुण शक्तियों को अपनी बुद्धि में समाहित करने वाले हनुमान जी अनेक आध्यात्मिक शक्तियों से सुसंपन्न रहे, लेकिन अपनी किसी भूल के कारण उन्हें यह शाप मिला कि समय आने पर वे अपनी शक्तियों को भूल जायेंगे और किसी के द्वारा याद दिलाये जाने पर वे शक्तियां जाग्रत हो उठेंगी। अब यह तो हम सब भलीभांति जानते ही हैं कि शाप देने का कार्य कोई श्रेष्ठ व्यक्ति तो कर नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि शाप या बददुआ देने वाली तो माया है, अर्थात पांच विकार, तो इसका अर्थ यह हुआ की कलियुग के अंत में जब हम सभी आत्माएं माया द्वारा शापित होकर मूर्च्छित हो जाती हैं और अपनी समस्त शक्तियां खो देती हैं, तब सर्वशक्तिमान परमात्मा हमें ज्ञान संजीवनी द्वारा फिर से सुरजीत करते हैं और माया के शाप से हमें सदा के लिए मुक्त कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपनी सर्व आध्यात्मिक शक्तियों को पुन: प्राप्त कर लेते हैं।

कहते हैं कि इष्ट का उज्जवल चरित्र ही साधकों के जीवन को इत्र समान खुशबूदार और गुणवान बनाता है। आत्मा अमर है और उसके द्वारा किए जाने वाले महान चरित्र भी चिरंजीव ही रहते हैं।

अत: हमें यह महसूस करना चाहिए कि वर्तमान समय वही युग परिवर्तन की वेला है, जब सर्व शक्तिमान परमात्मा माया रावण के चंगुल में फंसी आत्मा रूपी सीताओं की खोज में धरती पर अवतरित हो चुके हैं। ऐसे समय में भगवान श्री हनुमान जी की तरह त्याग, तपस्या और सेवा को जीवन में धारण करके ईश्वरीय सेवा में मददगार बनने वाली आत्माओं का भगवान आहान कर रहे हैं।

याचना की बजाय गुणों को धारण करें :

संसार की आत्माएं तो हुनमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की पूर्ति की कामना हेतु स्वार्थवश याद करती हैं, परन्तु वर्तमान समय की मांग यह है कि हम समय की नाजुकता को पहचान कर हनुमान जी से याचना करने की बजाय उन जैसे गुणों को धारण करके अनेक याचक आत्माओं की कामना पूर्ति करें और श्री हनुमान जी के गुणों की रोशनी से अपने जीवन-पथ को आलोकित करें। उनके समान ईश्वर प्रेम में रम जाएं और उनके समान ईश्वर समर्पित होकर ईश्वर समान बन जाएं।

दुर्योधन को भी दिए थे श्रीहरि ने विराट रूप में दर्शन



विश्वरूप या कहें भगवान विष्णु का विराट स्वरूप का उल्लेख भगवद्गीता के अध्याय 11 में है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्वरूप दर्शन कराते हैं। लेकिन उन्होंने इस रूप में पहले भी अपने भक्तों को दर्शन दिए है।

पुराणों में उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु ने अपने इस रूप के दर्शन लक्ष्मी जी को करवाए थे। हालांकि कि इस बारे में अलग-अलग पुराणों में अलग-अलग जानकारी मिलती है। भगवान विष्णु के परम भक्त नारद जी को भी उन्होंने अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए हैं। भगवान विष्णु के भक्त प्रहाद के वंशज थे राजा बलि। जिनको भगवान विष्णु ने वामन अवतार में विराट स्वरूप के दर्शन दिए थे। द्वापर युग में जब भगवान श्रीकृष्ण के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया तब उन्होंने अपनी मां यशोदा को भी इसी विराट स्वरूप में दर्शन दिए थे। महाभारत में दुर्योधन और विश्वरूप दर्शन वर्णित है। कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान अर्जुन को विराट रूप के दर्शन दिए।

भगवान विष्णु के अन्य नाम :

उग्र, शर्व, भगवत, नारायण, कृष्ण, वैकुण्ठ, विष्टरश्रवस्, जिन, हषिकेश, केशव, माधव, स्वभू, दैत्यारि, पुण्डरीकाक्ष, गोविन्द, गरुडध्वज, पीताम्बर, अच्युत, शार्गि, विष्वक्सेन, जनार्दन, दामोदर, इन्द्रावरज, चक्रपाणि, चतुर्भुज, पझानाभ, मधुरिपु, भीम, त्रिविक्रम, देवकीनन्दन, शौरि, श्रीपति, पुरुषोत्तम, वनमालिन्, बलिध्वंसिन, कंसाराति, अधोक्षज, विश्वम्भर, कैटभजित, विधु, श्रीवत्सलाञ्छन, पुराणपुरुष, यज्ञपुरुष,नरकान्तक, जलशायिन्, मुकुन्द, उपेन्द्र, मुरमर्दन, राम, वामन, नरसिंह, वराह और भविष्य में होने वाला अवतार कल्कि यह अवतार भगवान विष्णु का ही अवतार है।

क्यों अपनी ही पुत्री की ओर आकर्षित हुए ब्रहमा



सरस्वती का अर्थ होता है बहाव। यह बहाव केवल पानी का नहीं बल्कि विद्या और कला का भी है। यही वजह है कि इन्हें विद्या और कला की देवी भी कहा जाता है। सरस्वती के द्वारा विज्ञान, संगीत और कविताओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में सरस्वती को दैवीय नदी की भी संज्ञा दी गई है। साथ ही इन्हें पवित्रता और उर्वरता की देवी भी कहा गया है। सरस्वती को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जिनमें भागेश्वरी, सतरूपा, ब्राहमी, पृथुदर, बकदेवी, बिरज, शारदा आदि प्रमुख हैं। हिन्दू धर्म से जुडे पौराणिक इतिहास पर नजर डालें तो कई ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिनसे अभी तक आमजन वाकिफ नहीं हैं। विस्तृत इतिहास होने की वजह से कुछ घटनाएं छूट जाती हैं तो कुछ नजरअंदाज कर दी जाती हैं। इन्हीं कहानियों में से एक हैं सृष्टि के रचयिता ब्रहमा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की घटना।यह बात तो हम सभी जानते हैं कि त्रिदेव के हाथों में ही इस सृष्टि की बागडोर समाहित है। ब्रहमा के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है तो विष्णु के पास संरक्षण का, वहीं देवों के देव कहे जाने वाले महादेव शिव को विनाश का जिम्मा सौंपा गया है। इसी विनाश के बाद फिर से शुरू होता है सृजन का चक्र। ब्रहमा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रहमा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं केवल पिता, ब्रहमा थे।

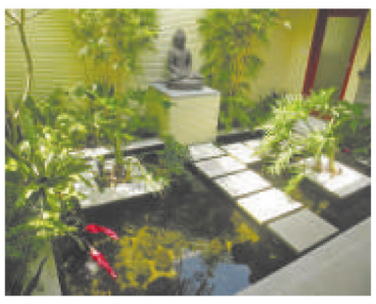
सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थीं कि स्वयं ब्रहमा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारो दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पडा। ब्रहमा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति-पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया था स्वयंभु मनु। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रहमा के पांच सिर थे। कहा जाता है जब ब्रहमा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रहमांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सान्ध्य, ब्राहमी को उत्पन्न किया। ब्रहमा अपनी ही बनाई हुई रचना, सरवस्ती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रहमा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारो दिशाओं में छिपती रहीं लेकिन वह उनसे नहीं बच पाईं इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं लेकिन अपने पांचवें सिर से ब्रहमा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रहमा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है।

प्रजापति ब्रहमा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उसके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं की नजरों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रहमा ने अपनी पुत्री के लिए यौनाकांक्षाएं रखीं, जोकि एक बडा पाप है, ब्रहमा को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आकर शिव ने उनके पांचवें सिर को उनके धड से अलग कर दिया था। शिव पुराण के अनुसार ब्रहमा के सर्वप्रथम पांच सिर थे। लेकिन जब अपने पांचवें मुख से उन्होंने सरस्वती जोकि उनकी पुत्री थी, को उनके साथ संभोग करने के लिए कहा तो क्रोधावश सरस्वती ने उनसे कहा कि तुम्हारा यह मुंह हमेशा अपवित्र बातें ही करता है जिसकी वजह से आप भी विपरीत ही सोचते हैं। इसी घटना के बाद एक बार भगवान शिव, अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रहमा के पास पहुंचे तो पांचवें सिर को छोडकर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि पांचवें मुख ने अमंगल आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इसी कारणवश क्रोध में आकर शिव ने ब्रहमा के पांचवें सिर को उनके धड से अलग कर दिया।

घर में इसलिए रखते हैं हरे पौधे

घर में यदि आप हरे पौधों को रखते हैं, तो यह घर के वास्तु दोषों को दूर करने में सहायक होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा तुलसी के पौधे को महत्व दिया जाता है। तुलसी के पौधे से जब हवा स्पर्श कर बहती है, तब वह घर के पर्यावरण को भी स्वस्थ्य रखती है। प्रदूषण और रोग निवारण में तुलसी का पौधा औषधि है। इस घर में अवश्य ही लगाएं। ठीक इसी तरह पृथ्वी के नीचे कहीं-कहीं निगेटिव स्ट्रीम(झिर) होती है। यदि यह स्ट्रीम दुकान या फैक्ट्री पर हो तो गंभीर रोगों से प्रभावित हो सकता है। यह गंभीर रोग जैसे हदय रोग, मधुमेह, लकवा और केंसर हो सकते हैं। तुलसी का पौधा यदि घर में है तो यह स्ट्रीम निष्क्रीय हो जाती है।

हरे पौधे विकास का प्रतीक भी माने जाते हैं। जो घर के अंदर रखने से मंगलमय यानी सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। ठीक इसी तरह वास्तु शांति के लिए घर के अंदर हवन भी हर माह जरूर करवाना चाहिए। हवन का धुंआ घर में उपस्थित निगेटिव एनर्जी, वास्तु दोषों के साथ रोग फैलाने वाले कीटाणुओं का भी अंत कर देता है। जिससे



कि आपकी जिंदगी खुशनुमा तरीके से व्यतीत होती है।

इन उपायों से होगी आपकी कई मनोकामनाएं पूरी

हमारे जीवन में सुख दुख तो लगा रहता है जिस कारण हम परेशान भी होते है । सभी चाहते हैं कि उसके जीवन में खुशहाली रहे और सुख-शांति बनी रहे पर हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। जीवन में सुख और शांति का बना रहना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में कुछ उपायों को अपनाकर शायद हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तुलसी के पौधे को प्रतिदिन जल चढाएं तथा गाय के घी का दीपक लगाएं। रविवार को पुष्य नक्षत्र में श्वेत आक की जड लाकर उससे श्रीगणेश की प्रतिमा बनाएं फिर उन्हें खीर का भोग लगाएं। लाल कनेर के फूल तथा चंदन आदि के उनकी पूजा करें। तत्पश्चात गणेशजी के बीज मंत्र (ऊँ गं) के अंत में नम: शब्द जोडकर 108 बार जप करें। सुबह गौरी-शंकर रुद्राक्ष शिवजी के मंदिर में चढाएं। सुबह बेल पत्र (बिल्ब) पर सफेद चंदन की बिंदी लगाकर मनोरथ बोलकर शिवलिंग पर अर्पित करें। बड के पत्ते पर मनोकामना लिखकर बहते जल में प्रवाहित करने से भी मनोरथ पूर्ति होती है। मनोकामना किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। नए सूती लाल कपडे में जटावाला नारियल बांधकर बहते जल में प्रवाहित करने से भी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इन प्रयोगों को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। सुबह घर से काम के लिए निकलने से पहले नियमित रूप से गाय को रोटी दें। एक पात्र में जल लेकर उसमें कुंकुम डालकर बरगद के वृक्ष पर नियमित रूप से चढाएं। सुबह घर से निकलने से पहले घर के सभी सदस्य अपने माथे पर चन्दन तिलक लगाएं। मछलियों की आटे की गोली बनाकर खिलाएं। चींटियों को खोपरे व शकर का बूरा मिलाकर खिलाएं। शुद्ध कस्तूरी को चमकीले पीले कपडे में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

बांग्लादेशः राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने दिया इस्तीफा

बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. संविधान के अनुच्छेद 50 (3) के तहत उन्होंने स्पीकर को हस्ताक्षरित इस्तीफा सौंपा, जिसे शुक्रवार शाम स्वीकार कर लिया गया. शहाबुद्दीन हाल में तब विवादों में आए थे, जब लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से संपर्क करने की कोशिश की थी. इसके बाद उनकी राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठे थे.हालांकि इस्तीफे की वजह पूछे जाने पर शहाबुद्दीन ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया और इससे अधिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. इससे पहले उनके इस्तीफे की अटकलें तेज थीं. वर्तमान में बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री हैं, रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मई 2026 में लंदन में इलाज के दौरान निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से फोन पर बात करने की कोशिश की थी।

मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया



नईदिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और उससे जुड़े विवाद के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा कि मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट हर नागरिक के लिए खुला है और किसी भी मामले की सुनवाई से कभी इनकार नहीं करता. यूएनसीआईटीआरएएल कॉन्फ्रेंस के इतर आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सभी लोगों के लिए खुला है. हम 24 घंटे, सातों दिन उपलब्ध हैं. सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी भी मुद्दे पर सुनवाई करने से इनकार नहीं करता. चीफ जस्टिस ने बताया कि छात्र आंदोलन से जुड़ी जिन याचिकाओं का शुक्रवार को अदालत के समक्ष उल्लेख किया गया, उन्हें सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है.चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत सभी के लिए खुली है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना भी जरूरी है।

बिना इजाजत रीपोस्ट नहीं होंगे कोर्ट के वीडियोः सुको



नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड और ऑनलाइन सुनवाई के ऑडियो-वीडियो प्रसारण को लेकर सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने नए अंतरिम निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पहले से अनुमति के बिना अदालत की कार्यवाही की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, अपलोड, ब्रॉडकास्ट/ टेलीकास्ट, रीपोस्ट, रिकॉर्ड, मॉडिफाई या मोनेटाइज नहीं किया जा सकेगा. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे, उन्होंने अदालत की कार्यवाही के वीडियो के अनथोराइज्ड इस्तेमाल और उनके मोनेटाइजेशन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.कोर्ट ने कहा कि संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल या सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल की पूर्व अनुमति के बिना कोर्ट की लाइव-स्ट्रीम की गई।

बीमारी रूट में है, इलाज फ्रूट का हो रहा है



नई दिल्ली। पेपर लीक के मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के बीच इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है. अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब बीमारी रुट में है तो फ्रूट के इलाज से कोई नहीं माननेवाला. देश में हर समस्या की एक ही जड़ है, जो गई अड़ है = नाम तो सुना होगा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों को लेकर बड़ा फैसला घोषित किया था. उन्होंने कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए देशभर में फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, ताकि दोषियों को जल्द और कड़ी सजा मिल सके. प्रधानमंत्री ने संबंधित विभागों को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं।

वंदे मातरम् के गायन में बाधा डालने पर होगी जेल



नई दिल्ली। विपक्ष के विरोध और जोरदार हंगामे के बीच गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने वंदे मातरम बिल राज्यसभा में पेश कर दिया. इस बिल पर चर्चा की शुरुआत नहीं हो सकी. संसद के मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया है. शुक्रवार को भी दोनों सदनों में चर्चा की शुरुआत नहीं हो सकी और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करने का ऐलान चेयर से कर दिया गया. राज्यसभा में शुक्रवार को कार्यवाही स्थगित होने से पहले गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया.विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच पेश हुए इस बिल पर चर्चा की शुरुआत नहीं हो सकी. हंगामे के कारण उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही न27 जुलाई, सोमवार को दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी. इस बिल के जरिये राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान जन गण मन की ही तरह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को भी कानूनी सुरक्षा देने का प्रावधान जोड़ा जाना है.

नीट विवादः किरण रिजिजू ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा,

राष्ट्र निर्माण में आपका योगदान...



नईदिलली। नीट-यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर देश भर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बाद, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जनसेवा और छात्रों के कल्याण के प्रति उनके जीवन भर के समर्पण की तारीफ़ की है। 25 जुलाई को ङ्क पर पोस्ट करते हुए, रिजिजू ने प्रधान के राजनीतिक करियर को सच्ची लीडरशिप का उदाहरण बताया और अपने कार्यकाल के दौरान भारत की शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने में उनके काम की तारीफ़ की। उन्होंने प्रधान की लगातार सेवा, सुधारों पर ध्यान देने और राष्ट्र-निर्माण में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

रिजिजू ने अपनी पोस्ट में लिखा कि असली लीडरशिप की पहचान दशकों में होती है और धर्मेंद्र प्रधान जी का सफ़र सार्वजनिक जीवन और छात्रों के कल्याण के लिए उनके जीवन भर के समर्पण का सबूत है। केंद्रीय कैबिनेट में उनके साथ काम करते हुए, मैंने भारत के शिक्षा सिस्टम को मज़बूत करने और हर फ़ैसले में लाखों युवा छात्रों को प्राथमिकता देने के प्रति उनकी सच्ची लगन देखी है। इतने अहम सेक्टर की अगुवाई करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत और लगन की ज़रूरत होती है, और उन्होंने इसे साहस और साफ़ सोच के साथ निभाया। धर्मेंद्र जी, आपकी लगातार सेवा, सुधारों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और एक मज़बूत भारत बनाने में आपके योगदान के लिए आपका धन्यवाद। मैं कामना करता हूँ कि आप इसी जोश और ईमानदारी के साथ देश की सेवा करते रहें! अखबार

प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफ़ा सौंपते हुए कहा कि उन्होंने यह फ़ैसला छात्रों के व्यापक हित में लिया है, ताकि देश के युवाओं को भ्रम के जाल में फंसने से बचाया जा सके। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दिल से आभार जताया। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने और देश भर में अच्छी क्वालिटी वाली हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने में प्रधान की भूमिका की तारीफ़ की। ङ्क पर एक पोस्ट में सरमा ने कहा कि प्रधान ने भारत की सभ्यतागत भावना को फिर से स्थापित करने और भारत की शिक्षा प्रणाली को औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त करने के लिए अथक प्रयास किए हैं।

सरमा ने लिखा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर, उन्होंने भारत की सांस्कृतिक भावना को फिर से जगाने और हमारी शिक्षा व्यवस्था को औपनिवेशिक सोच से मुक्त करने के लिए अथक प्रयास किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता - जिसमें कई राजनीतिक चुनौतियां भी थीं - को राष्ट्र-निर्माण में उनके सबसे बेहतरीन योगदानों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने असम के लिए प्रधान के समर्थन का भी ज़िक्र किया और कहा कि जब भी राज्य को मदद की ज़रूरत पड़ी, केंद्रीय मंत्री हमेशा राज्य के साथ खड़े रहे। सरमा ने कहा कि जब भी असम को उनके समर्थन की ज़रूरत पड़ी, वे हमारे साथ खड़े रहे। उनका प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और सद्भावना मेरे लिए हमेशा बहुत मायने रखती है।

राहुल गांधी का अल्टीमेटम

धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से हटाएं पीएम मोदी



नईदिल्ली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों से मिलने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि छात्रों ने तीन ऐसी मांगें रखी हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन मांगें हैं, और इन मांगों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पहली मांग यह है कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, क्योंकि वे भ्रष्ट और अयोग्य हैं और अपने काम के लिए सही नहीं हैं। मिस्टर मोदी की कैबिनेट में इस बात पर चर्चा हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर किसी दूसरे मंत्रालय में भेज दिया जाए। भारत के छात्रों को यह मंजूर नहीं है।

राहुल ने दावा किया कि यह किसी को भी मंजूर नहीं है। इसकी वजह यह है कि प्रधान भ्रष्टाचार और भारत के बच्चों के भविष्य के साथ जो हुआ है, उसकी निशानी हैं। वे इस देश की सबसे कीमती चीज़ - यानी हमारे छात्रों और उनके भविष्य - की बर्बादी की निशानी हैं। इसलिए, धर्मेंद्र प्रधान को इधर-उधर करने, पीछे या आगे करने जैसी कोई बात नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही होगा। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी बात... यह युवती घायल है। कल मैंने आपको एक युवक दिखाया था जिसकी आँख में गोली लगी थी, और ऐसे हज़ारों युवा हैं जिनके पैर और सिर लाठीचार्ज में टूट गए हैं और जिनके शरीर में छर्रे लगे हैं।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ऐसा किया है - चाहे वे इसे आयोजित करने वाले हों या इसे अंजाम देने वाले - उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इस पूरे सिस्टम के मुखिया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों और देश के भविष्य के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए माफ़ी माँगनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को सरकार पर छात्रों के खिलाफ ''क्रूर कदम'' उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेट्रो, रास्ते, दुकानें और इंटरनेट बंद कर दिए, लेकिन वह प्रश्नपत्र लीक नहीं रोक पाए।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक 'पोस्ट' में कहा कि मेट्रो बंद करो। रास्ते बंद करो। दुकानें बंद करो। इंटरनेट बंद करो। खाना बंद करो। उन्होंने कहा कि अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि बस एक चीज बंद नहीं कर पाए, मोदी जी, प्रश्नपत्र लीक।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया !

दिल्ली पुलिस ने प्रेस कांफ्रेंस में किये कई बड़े खुलासे



नईदिल्ली। जंतर-मंतर पर पिछले कई सप्ताह से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, जांच में ऐसे 400 से अधिक पाकिस्तान-संचालित सोशल मीडिया हैंडल सामने आए हैं, जिन्हें एआई-जनित फर्जी सामग्री, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और भ्रामक पोस्ट फैलाने के आरोप में ब्लॉक किया जा चुका है।

दिल्ली पुलिस के डीसीपी (सेंट्रल) रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से संचालित कई सोशल मीडिया अकाउंट जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ी झूठी और भ्रामक सामग्री को सुनियोजित तरीके से वायरल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे और खातों की पहचान करने में लगातार जुटी हुई है।

पुलिस के अनुसार, अब तक 400 से अधिक ऐसे हैंडल ब्लॉक किए जा चुके हैं, जो एआई-निर्मित कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड फोटो और अन्य भ्रामक सामग्री के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि इनमें से कुछ हैंडल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फर्जी सूचनाएं फैलाने में सक्रिय थे। इतना ही नहीं, इन अकाउंट्स पर कई वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक बयानों को एडिट कर गलत तरीके से पेश करने और दृश्य सामग्री से छेड़छाड़ करने के आरोप भी सामने आए हैं।

डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने लोगों से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर पोस्ट पर आंख मूंदकर भरोसा न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी वीडियो, फोटो या पोस्ट केवल वायरल होने भर से सत्य नहीं हो जाती। किसी भी जानकारी पर विश्वास करने या उसे आगे साझा करने से पहले उसकी तथ्य-जांच करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रख रही है और अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेक न्यूज, एआई-आधारित दुष्प्रचार, डीपफेक वीडियो, एडिटेड क्लिप और भ्रामक पोस्ट से जुड़ी सही जानकारी साझा कर रही है, ताकि लोग सच और झूठ के बीच स्पष्ट अंतर कर सकें।

देखा जाये तो जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच सामने आए ये खुलासे इस बात की गंभीर चेतावनी हैं कि डिजिटल दौर में दुष्प्रचार का हथियार पहले से कहीं अधिक खतरनाक हो चुका है। ऐसे में केवल वायरल सामग्री के आधार पर राय बनाना या उसे आगे बढ़ाना न केवल भ्रम फैलाने का माध्यम बन सकता है, बल्कि समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौती पैदा कर सकता है।

खेल
प्रमुख समाचार

झंडू कुमार के कांस्य पदक जीतने पर मोदी ने दी बधाई



नईदिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने ग्लासगो में आयोजित पुरुषों की हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश को पहला मेडल दिलाया। उनकी इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर झंडू कुमार की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, झंडू कुमार का शानदार प्रदर्शन। उन्होंने पुरुषों की हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पदक खाता खोला है। उन्हें बहुत-बहुत बधाई। उनकी उपलब्धि अद्भुत ताकत, अटूट संकल्प और वर्षों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने हर चुनौती को पार कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया है और करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया है।

झंडू कुमार ने प्रतियोगिता में 190 किलोग्राम का सफल लिफ्ट करते हुए 130.9 अंक हासिल किए और कांस्य पदक अपने नाम किया।उन्होंने पहले प्रयास में 181 किलोग्राम वजन उठाया, जिससे उन्हें 124.7 अंक मिले। दूसरे प्रयास में उन्होंने 190 किलोग्राम उठाकर कुछ समय के लिए बढ़त भी हासिल कर ली।

स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद में झंडू कुमार ने अंतिम प्रयास में 196 किलोग्राम वजन उठाने का फैसला किया। अगर वह इसमें सफल हो जाते तो बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड भी टूट जाता। हालांकि वह इस प्रयास में सफल नहीं हो सके और अंततः कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। झंडू कुमार का यह कांस्य पदक कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला पदक है। साथ ही यह इस संस्करण में पैरा पावरलिफ्टिंग में भारत का पहला पोडियम फिनिश भी साबित हुआ।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

टाटा कंज्यूमर का शुद्ध लाभ जून तिमाही में 29% बढ़ा

नई दिल्ली। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीसीपीएल) का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून पहली तिमाही में सालाना आधार पर 28.77 प्रतिशत बढ़कर 427.19 करोड़ रुपए रहा। टाटा समूह की रोजमर्रा के उपयोग की घरेलू वस्तुएं बनाने वाली कंपनी (एफएमसीजी) ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 331.75 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 12 प्रतिशत बढ़कर 5,348.88 करोड़ रुपए हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,778.91 करोड़ रुपए थी। अप्रैल-जून तिमाही में टीसीपीएल का कुल खर्च 10.9 प्रतिशत बढ़कर 4,828.61 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी की कुल आय 12.46 प्रतिशत बढ़कर 5,420.82 करोड़ रुपए रही।

अडानी ने एयरलाइन शुरू करने से किया इनकार

नई दिल्ली। अडानी ग्रुप ने भले ही एयरलाइन शुरू करने की खबरों से इनकार किया हो, लेकिन उसकी एयरपोर्ट कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कुछ नियमों में छूट देने की मांग की है। कंपनी का कहना है कि वह भविष्य की एयरलाइन के विकास में अहम भूमिका निभा सकती है और मौजूदा नियमों में बदलाव की जरूरत है। अडानी एयरपोर्ट्स के सीईओ अरुण बंसल ने जून में एएआई को लिखे पत्र में कहा कि ग्रुप की इकाई अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस एयरलाइन कारोबार में उतरने पर विचार कर रही थी। उन्होंने बताया कि ग्रुप के पास पायलट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, ग्राउंड हैंडलिंग और आठ एयरपोर्ट का मजबूत नेटवर्क है, जिससे वह एविएशन सेक्टर को नई दिशा दे सकता है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 676.24 अरब डॉलर के पार पहुंचा

मुंबई। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बेहद सकारात्मक खबर आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर बढ़त की राह पर है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, 17 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 1.08 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 676.237 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। यह लगातार दूसरा हफ्ता है जब देश के विदेशी भंडार में मजबूत सुधार देखा गया है। इससे पिछले सप्ताह में भी इसमें 964 मिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई थी। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक सांख्यिकीय पूरक के मुताबिक, इस समीक्षाधीन अवधि में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 4.549 अरब डॉलर बढ़कर 551.057 अरब डॉलर हो गईं।

जून में क्रेडिट कार्ड खर्च 2 लाख करोड़ रुपए के पार

नईदिल्ली। देश में क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च जून में लगातार दूसरे महीने 2 लाख करोड़ रुपए के स्तर से ऊपर बना रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जून में कुल क्रेडिट कार्ड खर्च सालाना आधार पर 9.8% बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि, यह मई के 2.02 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले मामूली कम रहा। क्रेडिट कार्ड खर्च में एचडीएफसी बैंक और एसबीआई कार्ड का प्रदर्शन सबसे मजबूत रहा। एचडीएफसी बैंक ने 16.2% की सालाना बढ़ोतरी के साथ 59,432 करोड़ रुपए का खर्च दर्ज किया, जबकि एसबीआई कार्ड का खर्च 34.4% बढ़कर 41,077 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं, आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड खर्च में 5.2% की सालाना गिरावट दर्ज की गई और यह 31,410.9 करोड़ रुपए रहा।

आयात निर्भरता घटाने पर जोर, आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा

डॉ. पी एस चोहरा

पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक नीतियों ने आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और लचीली अर्थव्यवस्था के निर्माण पर विशेष बल दिया है। अनेक सुधारों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत अब केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि विश्व का एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा, ऊर्जा अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव ने स्पष्ट किया है कि आयात पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक जोखिम बन सकती है। इसलिए, स्थानीय उत्पादन बढ़ाना और रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। भारत की वर्तमान आर्थिक नीति इसी दूरदर्शी सोच का प्रतिबिंब दिखाई देती है।

इस नीति का उद्देश्य आयात पर कृत्रिम प्रतिबंध लगाना नहीं है। यह उन क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है, जहां भारत के पास प्रतिस्पर्धी लागत, तकनीकी क्षमता और विशाल घरेलू बाजार का लाभ उपलब्ध है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कुल आयात लगभग 776 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। यह आंकड़ा बताता है कि भारत के आयात का आकार लगातार बढ़ा है। इस कारण व्यापार घाटा चुनौती बना हुआ है। ऐसे में, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना एक व्यावहारिक और आवश्यक रणनीति है।

इसी सोच के तहत आर्थिक नीतियों को नया रुख देते हुए लगभग 1,272 उत्पादों की पहचान की गई है, जिनका भारत प्रतिवर्ष लगभग 189 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात करता है और जो उसके कुल आयात का करीब 26 प्रतिशत है। इन क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर आयात बिल में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। इससे



विदेशी मुद्रा की खपत भी कम होगी। वहीं, भारत के कुल आयात का लगभग 46 प्रतिशत कच्चे तेल, सोना और कोयला जैसे संसाधनों पर खर्च होता है।

प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण निकट भविष्य में इनका आयात जारी रहना लगभग अपरिहार्य है। इसलिए, नीति का उद्देश्य उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है, जहां घरेलू उत्पादन वास्तविक रूप से संभव और आर्थिक रूप से लाभकारी है। लगभग 28 प्रतिशत आयात ऐसे उत्पादों का है, जिनका निर्माण भारत में पहले से हो रहा है, लेकिन विदेशी उत्पाद कई मामलों में अधिक प्रतिस्पर्धी साबित हो रहे हैं।

इसलिए, भारत के सामने चुनौती इन उत्पादों की विश्वस्तरीय गुणवत्ता, अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी नवाचार, लागत दक्षता और उत्पादकता विकसित करने की भी है, ताकि भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में भी प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस रणनीति की सफलता में राज्यों को केंद्रीय नीतियों के साथ तालमेल बिठाना होगा। साथ ही, निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस, भूमि उपलब्धता, सरल नियम, निवेश-अनुकूल नीतियां और नियामकीय सुधार लागू करने होंगे। केंद्र को इस उद्देश्य के लिए राज्यों को वित्तीय मदद उपलब्ध करानी होगी।

फरवरी 2026 के बाद से रुपया डॉलर के मुकाबले 96 रुपये प्रति डॉलर से अधिक के स्तर तक कमजोर हुआ है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी सात प्रतिशत की कमी हो चुकी है। रुपये की कमजोरी का अर्थ है कि समान मात्रा में आयात के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है। यदि आयात निर्भरता कम होगी, तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव भी कम होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों का अधिक मजबूती से सामना कर सकेगी। इस नीति के लाभ अनेक स्तरों पर दिखाई देंगे।

सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना के तहत मड़ानार और मर्दापाल में 238 छात्राओं को मिली साइकिलें

शिक्षा भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला : कश्यप



रायपुर। सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक कल्याणकारी पहल हैद्य इस योजना के तहत कक्षा 9वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) परिवारों की छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए नि:शुल्क साइकिल प्रदान की जाती है द्य

छत्तीसगढ़ शासन की नि:शुल्क सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना के तहत कोण्डागांव जिले के मड़ानार और मर्दापाल में 238 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं। इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।मड़ानार में आयोजित कार्यक्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़ानार, सोनाबाल और गोलावंड की 57 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गईं। वहीं मर्दापाल में मर्दापाल, हसलनार, मटवाल, कांगा, नवागांव और खड़पड़ी की 181 छात्राओं को योजना का लाभ मिला।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा ही उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला है। उन्होंने कहा कि शासन की सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना का उद्देश्य दूर-दराज के क्षेत्रों की छात्राओं को स्कूल आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराना और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने छात्राओं से मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ अध्ययन कर अपने सपनों को साकार करने का आह्वान किया।

प्रतिभाशाली का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। वन मंत्री ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अन्य विद्यार्थियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।

मंत्री श्री कश्यप ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनके संघर्ष के कारण देश को आजादी मिली। उन्होंने कहा कि बस्तर के वीर सेनानियों का भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विद्यार्थियों से उन्होंने देशभक्ति की भावना बनाए रखने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।

वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर क्षेत्र तेजी से विकास और शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस परिवर्तन में पुलिस एवं सुरक्षा बलों के योगदान की सराहना की।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीता शोरी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता कोर्राम, जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

दिव्यांशु देवांगन का वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया सम्मान



रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जूनियर वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल (मिक्स्ड डबल) स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज दिव्यांशु देवांगन के निवास पहुंचकर उनसे आत्मीय मुलाकात की और संवाद किया।इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने दिव्यांशु देवांगन को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया तथा उन्हें रामचरितमानस की प्रति भेंट करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दिव्यांशु ने अपनी प्रतिभा, अनुशासन और अथक मेहनत के बल पर विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। उनकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्रदेश और विशेष रूप से रायगढ़ के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।श्री चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि दिव्यांशु आने वाले समय में भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के लिए अनेक गौरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

दिव्यांशु देवांगन ने सम्मान एवं शुभकामनाओं के लिए वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा।

विपक्ष का मकसद समाधान नहीं, बल्कि देश में भ्रम और अराजकता फैलाना: देव



रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई ऐतिहासिक एवं कड़े कदमों की घोषणा तथा अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक द्वारा अनशन समाप्त किए जाने के बाद कांग्रेस सहित इण्डी गठबंधन के घटक दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन घटनाक्रमों ने विपक्ष के असली राजनीतिक चरित्र और उनके भारत विरोधी एजेंडे की पूरी तरह पोल खोल दी है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए त्वरित और अभूतपूर्व कदम उठाने की घोषणा की है। मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा न केवल त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्देश दिए हैं, बल्कि दोषियों को 5 से 10 साल की कड़ी सजा, कठोर जमानत शर्तों और दोषी पाए जाने पर संबंधित कोचिंग संस्थानों को बंद करने जैसे कठोर प्रावधानों वाले कानून का मसौदा तैयार करवाया जा रहा है। सरकार की इस त्वरित संवेदनशीलता और पारदर्शी नीयत के बाद केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने भी सरकार के सकारात्मक रुख पर भरोसा जताते हुए अपना अनशन समाप्त कर दिया। देव ने कहा कि यह पूरी घटना यह दर्शाती है कि मोदी-सरकार देश के छात्रों और युवाओं के हित में चट्टान की तरह खड़ी है। लेकिन दूसरी ओर, कांग्रेस और उनके सहयोगियों का एकमात्र एजेंडा छात्रों के कंधे पर बन्दूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकना और देश में असंतोष की आग भड़काना था।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि विपक्ष को कभी भी छात्रों के भविष्य या न्याय से कोई लेना-देना नहीं था। जब सरकार ने समस्या के जड़ से समाधान के लिए कड़ा कानून बनाने की दिशा में काम किया, तो इण्डी गठबंधन का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया। देव ने कहा कि देश के युवा समझदार हैं और वे देख सकते हैं कि कौन उनके भविष्य के लिए काम कर रहा है और कौन उनके नाम पर राजनीति कर रहा है? भाजपा सरकार देश के हर होनहार छात्र के हक की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

12 जिलों में 795 सहायक शिक्षकों की होगी भर्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य की शासकीय शालाओं में सहायक शिक्षक (तृतीय श्रेणी, वेतन मैट्रिक्स लेवल-06) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। राज्य स्तर पर लोक शिक्षण संचालनालय ने ई एवं टी संवर्ग मिलाकर कुल 2,292 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें मैदानी क्षेत्रों के 12 जिलों में ई-संवर्ग के कुल 795 पद शामिल हैं। प्रमुख जिलों में दुर्ग (80), बिलासपुर (80), बलौदाबाजार (80), बेमेतरा (70) और रायपुर (70) शामिल हैं। इसके अलावा अन्य जिलों के लिए भी रिक्तियां निर्धारित की गई हैं। आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए टी-संवर्ग के अंतर्गत 16 जिलों में कुल 1,497 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें जशपुर (150), बस्तर (125), बीजापुर (105), कांकेर (100) और कोण्डागांव (100) में सबसे अधिक रिक्तियां घोषित की गई हैं। इन जिलों में नियुक्ति के लिए भी व्यापमं के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विज्ञापन जारी होने के साथ ही डीएलएड एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों सहित शिक्षित बेरोजगार युवाओं में उत्साह का माहौल है। सहायक शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2026 की स्थिति में 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं राजनैतिक मजबूरी : बैज



रायपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं राजनैतिक मजबूरी है। धर्मेन्द्र प्रधान एवं भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता होती तो मार्च में जब नीट का पेपर लीक हुआ था उसी समय धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता। भाजपा ने हर संभव नीट के मामले को दबाने तथा युवाओं के अधिकार को कुचलने का काम किया, जब छात्र युवा विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार दबाव बनाने लगे देश भर में सरकार के खिलाफ आवाज उठी उसकी मजबूरी में धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा आया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जिस प्रकार से पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ आम जनता विरोध में है। छात्र नौजवान दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर देश के हर शहर में आंदोलन कर रहे है। यह बताता है कि सरकार जनता के विश्वास खो चुकी है। प्रधानमंत्री अपनी विफलता स्वीकार करें तथा तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। किसी प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ देश के युवाओं में ऐसा आक्रोश पहली बार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनभावना की कद्र करे इस्तीफा दें।

बैज ने कहा कि लाखों अभ्यर्थी भारी दबाव के बीच औसतन पांच वर्षों तक प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ाई कर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इस तैयारी में न केवल अभ्यर्थियों, बल्कि उनके परिवारों को भी भारी आर्थिक बोझ और त्याग का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अन्य अवसरों के दरवाजे उनके लिए बंद होते जा रहे है, इसलिए हर साल लगभग 9 करोड़ अभ्यर्थियों को केवल 6 लाख सरकारी नौकरियों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पेपर लीक का संकट अब एक राष्ट्रीय महामारी का रूप ले चुका है। मोदी की सरकार आने के बाद से देश में अब तक 150 से अधिक पेपर लीक की घटनाओं ने 7.5 करोड़ छात्रों और उनके परिवारों को सीधे प्रभावित किया है, लेकिन अब तक एक भी दोषी को सजा नहीं मिली है। लाखों अभ्यर्थी भारी दबाव के बीच औसतन पांच वर्षों तक प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ाई कर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इस तैयारी में न केवल अभ्यर्थियों, बल्कि उनके परिवारों को भी भारी आर्थिक बोझ और त्याग का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अन्य अवसरों के दरवाजे उनके लिए बंद होते जा रहे है, इसलिए हर साल लगभग 9 करोड़ अभ्यर्थियों को केवल 6 लाख सरकारी नौकरियों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

पीएम मोदी और केंद्रीय गृह शाह ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया: डॉ. रमन

रायपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर देशभर में युवाओं और छात्रों के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा था, उस पर



सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि यह निर्णय आंदोलन को शांत करने और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और भी सख्त कानून बनाए जाएंगे, ताकि किसी भी विद्यार्थी या युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार इस पूरे मामले में गंभीरता से आगे बढ़ रही है।

समाजसेवा के लिए पसंद पर नहीं, दायित्व पर हो फोकस: काले



रायपुर। महाराष्ट्र मंडल के नए कार्यकाल (2026-28) के पदाधिकारियों को उनके दायित?वों से सचिव चेतन दंडवते ने अवगत कराया और कार्यभार सौंपा। छत्रपति शिवाजी महाराज सभागृह में आहूत बैठक में अध्यक्ष अजय मधुकर काले ने कहा कि मंडल की विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों और महिला केंद्रों की संयोजिकाओं, सह संयोजिकाओं की संख्या 225 से भी अधिक है। ऐसे में यदि सभी पदाधिकारियों ने समर्पण भाव से अपने दायित्वों का निवर्हन किया, तो किसी भी कार्यक्रम में दर्शकों की कमी महसूस ही नहीं होगी। काले ने कहा कि प्रत्येक समिति को न्यूनतम दर्शकों को कार्यक्रमों में लाने की जिम्मेदारी दी है। साथ ही छह माह में कम से कम 25 नए सभासदों को महाराष्ट्र मंडल से जोड़ने का टारगेट भी दिया गया है। नए लोग संस्था से जुडेंगे, तो नए विचारों के साथ नई योजनाओं पर भी चर्चा और प्लानिंग होगी। अध?यक्ष ने कहा कि जरूरी नहीं कि सारे कार्यक्रम आपके पसंद के हों। यदि ऐसा कोई आयोजन, जिसमें आपकी रुचि नहीं है।

छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ करेगा 3 अगस्त को आंदोलन

रायपुर। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने डीजल के दामों में लगातार वृद्धि और यात्री किराए में की गई कटौती के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने साधारण बसों के किराए में 75 प्रतिशत और डिलक्स बसों के किराये में 30 प्रतिशत की वृद्धि की अधिसूचना तुरंत जारी करने के साथ ही महाराष्ट्र की तर्ज पर डीजल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के अनुसार किराया तय करने का स्थायी कानून बनाया जाए। मांग न मानने पर 3 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय के बस स्टैंडों पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि 14 अगस्त तक निर्णय नहीं लिया गया, तो पूरे छत्तीसगढ़ में अनिश्चितकालीन बस संचालन बंद कर दिया जाएगा। महासंघ का आरोप है कि परिवहन विभाग ने 11 मार्च 2025 की अधिसूचना के तहत बस किराए में लगभग 25 प्रतिशत की कटौती कर दी है। विभाग ने इसके पीछे उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया था, जबकि न्यायालय ने केवल चिल्हर की समस्या सुलझाने के लिए किराए को राउंड फिगर में तय करने का निर्देश दिया था। फिलहाल महासंघ आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। महासंघ का कहना है कि उच्च न्यायालय ने किराया कम करने का कोई आदेश नहीं दिया था लेकिन विभाग ने आदेश का त्रुटिपूर्ण अर्थ निकालकर किराए को घटा दिया, जिससे बस संचालकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

बिलासपुर-ओखा एक्सप्रेस का परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित



रायपुर । यात्रियों की सुरक्षित एवं सुगम रेल यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास एवं संरक्षा संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसी क्रम में पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल के अलियावाडा-हापा-जामनगर रेलखंड में लाइन दोहरीकरण का कार्य विभिन्न दिवसों में ब्लॉक लेकर किया जा रहा है ।इस कार्य के परिणामस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संचालित गाड़ी संख्या 22940 बिलासपुर-ओखा एक्सप्रेस का परिचालन निम्नानुसार आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। 27 जुलाई एवं 03 अगस्त को बिलासपुर से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 22940 बिलासपुर-ओखा एक्सप्रेस राजकोट स्टेशन पर समाप्त होगी तथा राजकोट-ओखा के मध्य रद्द रहेगी।

बाघ दिवस पर होगा रन फॉर इंद्रावती मैराथन का आयोजन

रायपुर। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों को बचाने के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है द्य बाघ हमारे पर्यावरण और जंगल के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। द्यअवैध शिकार और वनों की कटाई के कारण बाघों की जान को खतरा है, जिसे रोकने के लिए यह दिन प्रेरित करता है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप की पहल पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर एवं नोवा नेचर वेलफेयर सोसायटी, छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में 29 जुलाई 2026 के अवसर पर रन फॉर इंद्रावती मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों में बाघ, वन्यजीव, जैव विविधता एवं प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।यह मैराथन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व और वहां की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए जनभागीदारी और सामूहिक संकल्प का प्रतीक होगी।प्रतियोगिता 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दो श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। पुरुष एवं महिला वर्ग के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सुशासन को मिल रही नई मजबूती

शासन की पारदर्शी एवं जवाबदेह कार्यप्रणाली पर जताया विश्वास

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन की अवधारणा निरंतर सशक्त हो रही है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण हो। इसी उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आज नागरिकों और शासन के बीच विश्वास का सशक्त सेतु बनकर उभरी है। इसके माध्यम से लोगों की शिकायतों का गंभीरतापूर्वक निराकरण कर उन्हें बिना अनावश्यक परेशानी के सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने की दिशा में रायगढ़ जिला प्रशासन प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा



है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा और सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान प्राप्त हो।

इसी क्रम में रायगढ़ जिले के श्री रुद्रा बेहरा, श्री विश्वनाथन मोहन राव तथा श्री इलियास लोमगा ने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होते ही जिला परिवहन विभाग ने प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की। विभाग द्वारा सभी औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए तीनों शिकायतों का निर्धारित अवधि के भीतर सफलतापूर्वक निराकरण कर दिया गया।

समस्या का समाधान होने पर तीनों हितग्राहियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई हुई और बिना किसी अनावश्यक विलंब के समाधान मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आम नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से सरकारी सेवाएं अधिक सरल, सहज, पारदर्शी और प्रभावी रूप से उपलब्ध हो रही हैं। हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जिला प्रशासन तथा परिवहन विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस व्यवस्था की सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य केवल शिकायतों का निराकरण करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को यह विश्वास दिलाना है कि शासन उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन इसी जनहितैषी सोच का सशक्त माध्यम बनकर प्रदेश में सुशासन की नई कार्य संस्कृति स्थापित कर रही है। समयबद्ध कार्रवाई, पारदर्शी प्रक्रिया और नागरिक संतुष्टि पर आधारित यह व्यवस्था शासन और जनता के बीच विश्वास को निरंतर मजबूत कर रही है।

शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ेंगे 1200 बच्चे, तीन महीने के ब्रिज कोर्स से तय होगी कक्षा



रायपुर। अप्रवेशी और शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना एक जरूरी कदम है। इसके लिए घर-घर सर्वे कर बच्चों की पहचान करना, विशेष शिक्षण चलाना और माता-पिता को जागरूक करना मुख्य उपाय हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील नेतृत्व में और वन एवं प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार बीजापुर जिले के सुदूर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 1,200 शाला त्यागी (ड्रॉपआउट) और अप्रवेशी बच्चों को पुन: शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक विशेष पहल शुरू की है।कलेक्टर बीजापुर विश्वदीप और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नम्रता चौबे के निर्देशन में 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के इन बच्चों को पहचानकर आवासीय पोर्टा केबिनों में प्रवेश दिलाया गया है। घरेलू परिस्थितियों या स्थानीय समस्याओं के कारण पढ़ाई छोड़ चुके इन बच्चों को स्कूल के वातावरण में ढालने के लिए पहले खेलकूद, चित्रकला, नृत्य, टीवी और शैक्षणिक भ्रमण जैसी मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गई।बच्चों की शैक्षणिक क्षमता का आकलन करने और बुनियादी भाषा एवं गणित (संख्या ज्ञान) को मजबूत करने के लिए 90 दिनों का विशेष ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। ब्रिज कोर्स पूरा होने के बाद एक मूल्यांकन परीक्षा ली जाएगी, जिसके आधार पर बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार उचित कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वर्षों बाद इतनी बड़ी संख्या में बच्चे दोबारा पढ़ाई से जुड़ रहे हैं। प्रशासन की मंशा के अनुरूप इन बच्चों की देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.